



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2019/ज्येष्ठ 29, 1941

No. 169]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2019/JYAISTHA 29, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2019

अंतिम जांच परिणाम

(सी. सं. 04/2017)

विषय: दिनांक 01 जनवरी, 2018 को शुरू की गई जांच के संबंध में मैसर्स कीटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. (उत्पादक) और मैसर्स फोशान कैसीनो बिल्डिंग मैटेरियल कं. लि. (निर्यातक) द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेलामाइन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के नियम 22 के तहत न्यू शिपर समीक्षा।

फा.सं.7/11/2017-डीजीएडी.— समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) ने 28.01.2016 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 02/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा कार्यान्वित दिनांक 05.12.2015 की अधिसूचना संख्या 15/17/2014-डीजीएडी द्वारा संबद्ध सामानों पर चीन जन. गण. (संबद्ध देश) के मूल के अथवा वहां से भारत को निर्यातित "मेलामाइन" (जिसे यहां आगे संबद्ध सामान भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में दूसरी निर्णायक समीक्षा के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की। मूल पाटनरोधी शुल्क अंतिम जांच परिणाम

अधिसूचना संख्या 14/16/2003-डीजीएडी दिनांक 03.09.2004 और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 107/2004 दिनांक 16.11.2004 द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध सामानों पर लगाए गए थे। उसके बाद दिनांक 20.11.2009 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना 15/29/2008-डीजीएडी द्वारा पहली निर्णायक समीक्षा का निष्कर्ष निकाला गया था और 19.02.2010 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 10/2010-सीमा शुल्क द्वारा कार्यान्वित किया गया था।

3. प्राधिकारी ने दूसरी निर्णायक समीक्षा में संदर्भ कीमत के बजाए निर्धारित पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जो जांच के दौरान नोटिंग पर पहली निर्णायक समीक्षा के दौरान लगाई गई थी कि संदर्भ कीमत आयातकों द्वारा अधिक बीजक के माध्यम से प्रवंचित की जा रही थी। किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने दूसरी निर्णायक समीक्षा के दौरान सहयोग नहीं किया और पाटनरोधी शुल्क की उसी मात्रा की सिफारिश सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए की गई थी।

4. मैसर्स कीटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. (उत्पादक) और मैसर्स फोशान कैसीनो बिल्डिंग मैटेरियल कं. लि. (निर्यातक) (जिन्हें यहां आगे "न्यू शिपर" अथवा "आवेदक" कहा गया है) ने चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में दिनांक 28.01.2016 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 02/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के संबंध में न्यू शिपर समीक्षा (एनएसआर) के लिए अनुरोध करते हुए सीमा प्रशुल्क अधिनियम के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत पूर्ण आवेदन दायर किया।

5. अधिनियम और उसके तहत बनाई गई पाटनरोधी नियमावली में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे उस प्रश्रुत निर्यातक देश में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए न्यू शिपर समीक्षा करें जिसमें संबद्ध देश से मूल पाटनरोधी जांच की जांचावधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है और इसके अतिरिक्त यह कि आवेदक उस निर्यातक देश में किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन है। आवेदक ने दावा किया कि वे चीन में किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं जिनके विरुद्ध संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी उपाय लागू हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मूल जांच की जांचावधि के दौरान संबंधित उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।

6. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध की प्रथम दृष्टया जांच करने के बाद दिनांक 01.01.2018 की अधिसूचना फा. सं. 7/11/2017-डीजीएडी द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार न्यू शिपर समीक्षा जांच शुरू की।

7. वित्त मंत्रालय ने 20.03.2018 की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा उपर्युक्त एनएसआर जांच के पूरा होने तक संबद्ध सामानों के लिए आवेदकों द्वारा किए गए सभी निर्यातों का अनंतिम मूल्यांकन अधिसूचित किया।

8. इस न्यू शिपर समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 01 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक निर्धारित की गई थी।

क. प्रक्रिया

9. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- (i) प्राधिकारी ने संबद्ध एनएसआर पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 01 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 7/11/2017 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- (ii) प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली की प्रति सहित आवेदक को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उन्हें लिखित में अपने ज्ञात विचार देने तथा जांच की अवधि की समाप्ति के बाद निर्धारित प्रश्नावली में संगत आंकड़े दायर करने का अवसर प्रदान किया।
- (iii) प्राधिकारी ने नई दिल्ली, भारत में चीन जन. गण. दूतावास को भी जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी।
- (iv) प्राधिकारी ने भारत में ज्ञात घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उन्हें लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर प्रदान किया।
- (v) जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में प्रश्नावली का उत्तर आवेदक मैसर्स कीटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. (उत्पादक) और मैसर्स फोशान कैसीनो बिल्डिंग मैटेरियल कं. लि. (निर्यातक) द्वारा दायर किया गया था। तथापि, उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था स्तर का दावा करते हुए प्रश्नावली दायर नहीं की है।
- (vi) जांच प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा साक्ष्य से समर्थित सीमा तक उठाए गए और प्रस्तुत किए गए तर्क और वर्तमान जांच में संगत माने गए तर्क इस प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- (vii) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया गया था।
- (viii) प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार, मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने हेतु 14.02.2019 को मौखिक सुनवाई की। हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत

विचारों/सूचना के संबंध में खंडन प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।

- (ix) इसके अतिरिक्त, आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच की गई और डेस्क अध्ययन के माध्यम से उनका सत्यापन किया गया था तथा जहां अपेक्षित था, संगत समर्थन दस्तावेज मांगे गए थे।
- (x) प्राधिकारी ने नियम 16 के अनुसार 22.05.2019 को एक प्रकटन विवरण जारी किया और 03.06.2019 तक हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां आमंत्रित कीं। तथापि, समय विस्तार के अनुरोध पर प्राधिकारी ने 07.06.2019 तक समय बढ़ाया।
- (xi) *** विवरण में गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना और प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार पाटनरोधी नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाती है।
- (xii) 69.26 प्रति अम.डॉ. का विनिमय दर जांच की अवधि के लिए अपनाया गया है।

विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में उनके गोपनीयता के दावों की जांच की गई है जो सूचना प्रकृति में गोपनीय है अथवा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उसके गोपनीय सार सहित दी गई है, उसे गोपनीय माना गया है।

- (i) जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी संगत अनुरोधों/ टिप्पणियों पर विचार किया गया है और उन्हें प्रकटन विवरण में शामिल किया गया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

10. मूल तथा निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद "चीन के मूल का अथवा वहां से निर्यातित मेलामाइन, स्वादहीन, गंधहीन, नॉन-टॉक्सिक शुद्ध रासायनिक चूर्ण है। मेलामाइन की फॉर्मिलिडहाइड से प्रक्रिया की जाती है और सौंदर्य तथा उपयोगिता के असंख्य उत्पाद बनाने के लिए रेसिन्स अथवा मॉडिंग पाउडर में बनाया जाता है।"

11. मेलामाइन सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के तहत आईटीसी एचएस 29336100 के तहत वर्गीकृत है।

ग. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

12. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध:

- i. याचिकाकर्ता ने याचिका में विरोधाभासी और अस्पष्ट विवरण दिए हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता ने भारत को संबद्ध सामान का निर्यात किया है।
- ii. प्राधिकारी ने 25 अप्रैल, 2018 की पुरानी सूचना संख्या 08/2018 द्वारा एनएसआर आवेदनों के लिए एक नया प्रपत्र निर्धारित किया है। आवेदन पत्र पुराने प्रपत्र के अनुसार दायर किया गया है और आवेदक द्वारा प्रपत्र में आवेदन को अद्यतन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप आवेदन में महत्वपूर्ण सूचना का अभाव है जो कि जांच की शुरुआत की आवश्यकता का औचित्य बनाने के लिए और मामले के औचित्य का निर्णय लेने के लिए आवश्यक है।
- iii. कानून न्यू शिपर समीक्षा की आवश्यकता को मानता है तथा यदि आवेदक एनएसआर जांच की शुरुआत के लिए तीनों मानदंडों को पूरा करता है तो जांच की जाती है अर्थात् (क) वे उपयुक्त/अधिकृत निर्यातक हैं जिन्होंने अधिकृत बिक्री की है, (ख) उन्होंने मूल जांच में सामानों का निर्यात नहीं किया है और (ग) वे संबद्ध सामानों के उत्पादक/निर्यातक से संबंधित नहीं हैं जिस पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है। तथापि, आवेदक वर्तमान जांच में मानदंड को पूरा नहीं करते।
- iv. याचिका में फोशान कैसीनो बिल्डिंग मेटेरियल कं. लि. (निर्यातक) द्वारा नियम 22 के तहत पात्रता की शर्तों को पूरा करने के संबंध में कोई सूचना/आवश्यक साक्ष्य नहीं दिए गए हैं। अतः एनएसआर जांच की शुरुआत के लिए फोशान कैसीनो बिल्डिंग मेटेरियल कं. लि. की पात्रता के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।
- v. जांच 01 जनवरी, 2018 को शुरू की गई थी और आवेदक द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करना दर्शाने के लिए अभी तक रिकार्ड में कोई भी साक्ष्य नहीं रखे गए हैं। यदि जांच के इस विलंब के स्तर पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो घरेलू उद्योग कोई टिप्पणी नहीं कर पाएगा।
- vi. संभावित जांच की अवधि, वर्तमान जांच के अनुसार, अब उपयुक्त नहीं है और कानून के विरुद्ध है, जैसा कि सेसटेट द्वारा एचएंडआर जॉनशन (इंडिया) लिमिटेड बनाम वित्त मंत्रालय में उल्लेख किया गया है।
- vii. संभावित जांचावधि के कारण, आवेदक आंकड़ों में छेड़छाड़ करने और (क) गैर-महत्वपूर्ण कई लेन-देन करके, (ख) निर्यातों की काफी मात्रा करके, (ग) उच्च कीमतों पर कीमतें बनाने में सक्षम रहा है।

viii. अलग-अलग पाटन मार्जिन निकालने के लिए जांच की गई बिक्री प्रकृति में उपयुक्त होनी चाहिए। बिक्री अधिकृत वाणिज्यिक लेन-देनों की होनी चाहिए। उनका प्रयोग कुछ बनाई गई उच्च कीमत वाले लेन-देनों द्वारा छेड़छाड़ करके कम पाटन मार्जिन प्राप्त करने के लिए हथियार के रूप में ही नहीं किया जाना चाहिए।

ix. ब्राजील, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, ताइवान, यूरोपीय संघ और वियतनाम अधिदेश जैसे अन्य न्यायाधिकरण, कानून द्वारा आवेदक से अधिकृत निर्यातों की काफी/पर्याप्त मात्रा की मौजूदगी।

- एनएसआर के संबंध में ब्राजील के प्रावधानों में यह शामिल है कि छः माह की अवधि के भीतर आवेदक के उत्पाद का ब्राजीली आयातों की पर्याप्त मात्राओं की स्थिति में निर्यातक देश में समान उत्पाद की विनिर्माण लागत और सामान्य मूल्य के संबंध में सूचना ब्राजील में निर्यात मात्रा और कीमत संबंधी सूचना के अलावा आवेदन में शामिल की जाएगी तथा उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कोई समायोजन शामिल किया जाएगा। आवेदन पत्र ऊपर दी गई अवधि की समाप्ति से 4 माह तक दायर किया जाएगा। ब्राजील ने मेलामाइन के आयात के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लगाई हैं:
 - आवेदक के उत्पाद के ब्राजीली आयात छः माह की अवधि के भीतर होने चाहिए।
 - ये आयात पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए।
 - आवेदन पत्र उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से 4 माह की अवधि के भीतर होने चाहिए।
- चीन जन. गण. में भी यह प्रावधान है कि न्यू शिपर के लिए आवेदक को एक पक्षकार होना चाहिए जिसने वास्तविक रूप से जांच की मूल अवधि के बाद चीन जन. गण. को जांचाधीन उत्पाद का निर्यात किया हो। अनुच्छेद 5 के अनुसार न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदक को एक पक्षकार होना चाहिए जिसने वास्तव में जांच की मूल अवधि के बाद चीन जन. गण. को जांचाधीन उत्पाद का निर्यात किया हो। अनुच्छेद में उल्लिखित निर्यात पर्याप्त मात्रा में किए जाएंगे ताकि साधारण निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए आधार बनें। ये मात्राएं जांचाधीन उत्पाद की सामान्य वाणिज्यिक शर्तों के तहत लेन-देन की मात्रा के आधार पर सिद्ध की जाएंगी। आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें नीचे उल्लिखित हैं:
 - आवेदक ने जांच की मूल अवधि के बाद चीन को जांचाधीन उत्पाद का निर्यात वास्तविक रूप से किया ही हो।
 - साधारण निर्यात कीमत का निर्धारण करने देने के लिए निर्यात पर्याप्त मात्रा में किया ही जाना चाहिए।
 - भले ही निर्यात पर्याप्त मात्रा में किए गए हैं, वे सामान्य वाणिज्यिक शर्तों के तहत लेन-देन की मात्रा के आधार पर सिद्ध किए जाएंगे। चीनी कानून में यह भी प्रावधान है कि "न्यू शिपर समीक्षा के लिए जांच की अवधि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से छः माह पूर्व होगी।" घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि वर्तमान मामला चीन से संबंधित है और चीनी उत्पादक उससे अधिक अनुकूल व्यवहार की मांग नहीं कर सकते जो उसका अपना देश विदेशी उत्पादकों को देता है।
- अमेरिकी कानून में यह प्रावधान है कि निर्यातक ने संबद्ध सामानों का वास्तव में निर्यात किया ही हो अथवा निर्यात के लिए उत्पाद की बिक्री की हो जो कि न्यू शिपर समीक्षा के लिए अनुरोध करने हेतु एक पूर्व शर्त है। "अधिनियम की धारा 751(क)(2)(ख) की अपेक्षाओं के अधीन कोई निर्यातक अथवा उत्पादक न्यू शिपर समीक्षा का अनुरोध कर सकता है, यदि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को संबद्ध माल का निर्यात किया हो अथवा निर्यात के लिए बिक्री की हो।" न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदन दायर करने हेतु जांच सूची के पहले दो प्रश्न इस मुद्दे से भी संबंधित हैं:

"क. क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को संबद्ध माल का निर्यात किया है अथवा निर्यात के लिए बिक्री की है? (धारा 351.214(ख)(1))"

"ख. क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में खपत के लिए कोई प्रविष्टि की है अथवा संगत समीक्षा अवधि के दौरान किसी असंबद्ध ग्राहक को संबद्ध सामान की बिक्री की है (जांच की शुरुआत पर कार्रवाई करने के लिए न्यू शिपर समीक्षा अवधि के दौरान या तो कोई बिक्री होनी चाहिए या प्रविष्टि होनी चाहिए)? (धारा 351.214(च)(2)(i))?"

संयुक्त राज्य अमेरिका एक अधिकृत बिक्री परीक्षण करता है जो कि "चीन जन. गण. शंघाई सनव्यूटी ट्रेडिंग कं. लि. से शहद की पाटनरोधी शुल्क न्यू शिपर समीक्षा के अंतिम खंडन के लिए मुद्दे और निर्णय ज्ञापन" के अंतिम खंडन के लिए मुद्दों और निर्णय ज्ञापन के उद्धरणों से सिद्ध है [ए-570-863]; संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने अधिकृत बिक्री परीक्षण के प्रयोग को माना है। इस परीक्षण के पीछे यह तर्क इस तथ्य से सामान्य रूप से बनता है कि निर्यातक को कुछ लेन-देनों के आधार पर कम मार्जिन का लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यू शिपर

समीक्षा उनके व्यापार का प्रबंधन करके अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए निर्यातक के लिए एक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- यूरोपीय संघ के सदस्य न होने वाले देशों से पाटित आयातों के विरुद्ध संरक्षण के संबंध में 08 जून, 2016 के परिषद के तथा यूरोपीय संसद के विनियम (ईयू) 2016/1036 के अनुच्छेद 11(4) में न्यू निर्यातक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान है: "समीक्षा वहां शुरू की जाएगी जहां कोई नया निर्यातक अथवा उत्पादक यह दर्शा सके कि वह उस निर्यातक देश में किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है जो उत्पाद के संबंध में पाटनरोधी उपायों के अध्यक्षीन हैं और यह कि उसने वास्तव में जांच की अवधि के बाद संघ को निर्यात किया है अथवा जहां वह यह दर्शा सके कि उसने संघ को पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने के लिए अखंडनीय संविदागत दायित्व में प्रवेश किया है।" यूरोपीय संघ में यह भी अपेक्षा है कि समीक्षा वहीं शुरू की जाए जहां निर्यातक ने या तो संबद्ध सामानों का निर्यात किया हो अथवा यूरोपीय संघ को काफी मात्रा में निर्यात करने के लिए अखंडनीय संविदागत दायित्व पर सहमति की हो।

- तुर्की के यूरोपीय संघ की तरह ही समान प्रावधान है और न्यू शिपर समीक्षा के पात्र आवेदकों के संबंध में निम्नलिखित हैं:

"अनुच्छेद 8 – निश्चयात्मक उपायों के लिए निर्णय की समीक्षा नए उत्पादक/ निर्यातकों द्वारा अनुरोध पर की जाए जिन्होंने जांचावधि के दौरान संबंधित उत्पाद का निर्यात नहीं किया है और जो यह दर्शा सके कि वे उस किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं जिसका उत्पाद वर्तमान में निश्चयात्मक उपायों के अध्यक्षीन है। तथापि, इस प्रकार की समीक्षा का अनुरोध करने वाले उत्पादकों अथवा निर्यातकों ने जांचावधि के बाद तुर्की को संबंधित उत्पाद का या तो वास्तव में निर्यात किया हो अथवा उसकी पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने के लिए अखंडनीय संविदागत दायित्व पर सहमति दी हो। नई निर्यातक समीक्षा उनके लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने अथवा सब्सिडी की मात्रा निर्धारित करने के लिए बड़े हुए आधार पर की जाएगी जिन्होंने अनुरोध किया है।"

- ताइवान के प्रतिकारी तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने के कार्यान्वयन को शासित करने वाले विनियमों में भी यह प्रावधान है कि कोई भी निर्यातक तभी न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है यदि उस निर्यातक ने संबंधित उत्पाद की पर्याप्त मात्रा निर्यात की हो। इसके अतिरिक्त, निर्यातों की शुरुआत के बाद एक वर्ष के बाद ही आवेदन किया जा सकता है।

"अनुच्छेद 35 – मामले के विदेशी उत्पादक/निर्यातक संगत दस्तावेजों अथवा साक्ष्य के सबूत के साथ वित्त मंत्रालय को न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और अलग-अलग पाटन मार्जिन के लिए अनुरोध कर सकते हैं, बशर्ते कि:

- जांचावधि के दौरान ताइवान को संबंधित उत्पाद का कोई निर्यात न हो।
- वे दर्शा सकते हैं कि वे मामले के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादन से संबंधित नहीं हैं और उन्होंने जांचावधि के दौरान ताइवान को संबंधित उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।
- उन्होंने मूल जांचावधि के बाद ताइवान को संबंधित उत्पाद का पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया है।

- वियतनाम कानून के तहत यह अपेक्षित है कि न्यू शिपर समीक्षा के लिए दायर किया जाने वाला आवेदन निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा करे:

- आवेदक का शुल्क के अध्यक्षीन उत्पादकों/निर्यातकों से कोई संबंध नहीं है।
- आवेदक ने वास्तव में मूल जांच की जांचावधि के बाद वियतनाम को निर्यात किया है।
- वियतनाम को निर्यातों की मात्रा उपयुक्त निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी के लिए काफी है। निर्यातों की मात्रा आवेदन पत्र दायर करने के समय देखी जाएगी।

न्यू शिपर समीक्षा के मुद्दे के संबंध में वैश्विक परिपाटी इस दृष्टि से बहुत स्पष्ट है कि न्यू शिपर समीक्षा के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी की ही जानी चाहिए:

- आवेदक ने मूल जांच की जांचावधि के दौरान जांचकर्ता देश को संबद्ध सामानों का निर्यात न किया हो।
- आवेदक ने उस किसी भी उत्पादक/निर्यातक से संबंधित नहीं होना चाहिए जो विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन रहा हो।
- आवेदक ने मूल जांच की जांचावधि के बाद जांचकर्ता देश को संबद्ध सामानों का निर्यात किया हो।
- निर्यात पर्याप्त अथवा काफी मात्रा में किए गए होने चाहिए ताकि निर्यात कीमत प्रतिनिधिकारक हो; और
- ये निर्यात आवेदन पत्र दायर करने से पूर्व किए गए होने चाहिए।

x. घरेलू उद्योग ने "निर्यातों की वाणिज्यिक/काफी मात्रा" के संबंध में एनएसआर आवेदनों में भारतीय परिपाटी और न्याय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख किए हैं:

- भारतीय कानून में यह अपेक्षित नहीं है कि निर्यातक ने न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदन करने से पूर्व निर्यात किए ही हों; तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी की हाल की परिपाटी और न्यायालय के निर्णयों से वही निष्कर्ष निकलता है। यह नोट किया जाए कि आरंभिक तौर पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संभावित जांचावधि मानी थी। तथापि, इस परिपाटी पर भी दिनांक 15 फरवरी, 2007 के निर्णय में 2007 (2012) ई.एल.टी. 130 (ट्राई-डेल.) में सूचित एचएंडआर जॉनशन (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में अधिकरण द्वारा भी तेवर दिखाए गए थे।

xi. पुनः अपील संख्या 1/2007-पाटनरोधी में एचएंडआर जॉनशन (इंडिया) लिमिटेड बनाम वित्त मंत्रालय के मामले में 27 अगस्त, 2007 के निर्णय में अधिकरण ने स्पष्ट रूप से माना कि संभावित जांचावधि का प्रयोग न्यू शिपर समीक्षा के मामले में मुनासिब नहीं था। इसके अतिरिक्त, अधिकरण ने निर्धारित किया कि किसी निर्यातक के लिए न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

- न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदक को एक पक्षकार होना चाहिए जिसने वास्तव में मूल जांचावधि के बाद भारत को जांचाधीन उत्पाद का निर्यात किया हो।
- ये निर्यात पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए ताकि वे निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए आधार बनें।
- ये मात्राएं जांचाधीन उत्पाद की वाणिज्यिक शर्तों के तहत लेन-देन मूल्य के आधार पर सिद्ध की जाएंगी।
- सार्थक जांच के लिए न्यू शिपर के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने हेतु जांच की अवधि सामान्यतः आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की छः माह से 12 माह के बीच होनी चाहिए।

उपर्युक्त सिद्धांत हाल के जांच परिणामों में भी पाए गए हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया है कि न्यू शिपर द्वारा निर्यात काफी मात्रा में होने चाहिए ताकि वे प्रतिनिधिकारक कीमत का निर्धारण किया जा सके। इस संबंध में, दिनांक 22 नवंबर, 2018 के मैसर्स जनता जूट मिल्स (उत्पादक) के संबंध में बांग्लादेश से जूट उत्पादों के आयातों के संबंध में न्यू शिपर समीक्षा जांच के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के जांच परिणाम हैं।

xii. इसी प्रकार, दिनांक 26 जुलाई, 2018 [सं. 15/22/2016-डीजीएडी] के "मैसर्स झेजियांग सेनमेई केमिकल इंड. कं. लि. (उत्पादक/निर्यातक), मैसर्स झेजियांग सनमेई केमिकल प्रोडक्ट्स कं. लि. (निर्यातक) और मैसर्स जियांग्सु सनमेई केमिकल इंड. कं. लि. (उत्पादक) के संबंध में चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 1 1 1 2 टेट्राफ्लोरोथीन अथवा आर 134ए के आयातों के संबंध में न्यू शिपर समीक्षा जांच" में निर्दिष्ट प्राधिकारी का रिकार्ड निर्णय नोट किया जाए। उपर्युक्त मामले में संभावित जांचावधि शामिल थी, उपर्युक्त मामला स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि वह निर्यातक को कम पाटनरोधी शुल्क का लाभ लेने के लिए अनुमति दे सकता है।

xiii. "मैसर्स हैनिंग तियानफु वार्प निटिंग कं. लि., चीन जन. गण. (उत्पादक) और मैसर्स मन्ना, कोरिया गणराज्य (निर्यातक) द्वारा अनुरोध किए गए अनुसार चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी फ्लैक्स फिल्म के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में न्यू शिपर समीक्षा" [सं. 15/23/2011-डीजीएडी] में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाया कि निर्यातों की कम मात्रा होने की स्थिति में एक जोखिम था कि लेन-देन कम मार्जिन देने के लिए तैयार किए गए थे। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निर्यातक को अलग मार्जिन की अनुमति देने से इंकार कर दिया और उन्हें अवशिष्ट शुल्क में रखा गया था। उपर्युक्त विश्लेषण और चर्चाओं से यह सिद्ध है कि नियम 22 के तहत सूचीबद्ध शर्तें न्यू शिपर समीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई निर्यातक इस प्रक्रिया का अनुचित लाभ न ले, अधिकरण द्वारा सूचीबद्ध शर्तों को आवश्यक रूप से पूरा किया ही जाना चाहिए।

xiv. दिनांक 29 जनवरी, 2019 की व्यापार सूचना 01/2019 में भी एनएसआर जांच के दौरान अलग पाटन मार्जिन प्राप्त करने के लिए निर्यातों की वाणिज्यिक मात्रा की मौजूदगी के संबंध में परिपाटी स्पष्ट है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि एनएसआर आवेदन पर प्राधिकारी द्वारा तभी विचार किया जाएगा यदि एनएसआर आवेदक ने आवेदन करने से पूर्व संबंधित उत्पाद के लिए "वाणिज्यिक मात्राओं" में भारत को वास्तविक निर्यात किए हों।

xv. प्राधिकारी ने विशेष रूप से निर्धारित किया है कि निर्यातक द्वारा निर्यातित मात्राएं वाणिज्यिक मात्रा में होनी चाहिए ताकि अलग पाटन मार्जिन प्राप्त किया जा सके। यहां तक कि यद्यपि व्यापार सूचना प्रकृति में

संभावी है, तथापि उल्लिखित सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है। वास्तविक निर्यातों का सिद्धांत वाणिज्यिक मात्रा में किया गया है जिसे प्राधिकारी तथा माननीय सेसटेट ने विगत में भी माना है।

- xvi. उपर्युक्त नियम 22 की अन्य अपेक्षाओं के साथ निर्यात की वाणिज्यिक/काफी मात्रा की आवश्यकता न्यायालयों द्वारा कई निर्णयों में तथा प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम में दी गई है।
- xvii. आयात कीमत की उपयुक्तता सुनिश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि आयातकों से प्रश्नावली के कोई उत्तर नहीं हैं। इस संबंध में, मामले के विशिष्ट तथ्य तथा परिस्थितियां निर्यात कीमत को अविश्वसनीय बनाती हैं।
- xviii. प्रश्नावली के उत्तर में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। प्रश्नावली का अगोपनीय रुपांतर गोपनीयता संबंधी व्यापार सूचना, कानून और प्राधिकारी की परिपाटी के अनुरूप नहीं है।
- xix. अत्यधिक गोपनीयता और अपर्याप्त सूचना के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या आवेदक द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा किया गया है। इसके अतिरिक्त, बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए कोई दावा इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए कि निर्णायक समीक्षा के दौरान सामान्य मूल्य परिकलन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था आधार पर किया गया था।
- xx. यदि आवेदक यह मानते हैं कि निर्धारण घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए तो वह प्राधिकारी की परिपाटी के विरुद्ध होगा।
- xxi. व्यापार के चैनल में निर्यातक को शामिल करने के लिए आवेदक द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक द्वारा उसका उपयोग छेड़छाड़ के लिए किया जा सकता है और ऐसे सत्यापित न किए गए दावे रद्द किए जाने चाहिए।
- xxii. संभावित जांचावधि वर्तमान जांचों में औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि मूल जांचावधि के दौरान निर्यातों के अभाव के लिए आवेदक द्वारा कोई उचित तर्क नहीं दिया गया है।
- xxiii. निर्णायक समीक्षा में कोई उत्तरदाता निर्यातक नहीं थे और इसीलिए सभी चीनी निर्यातक अवशिष्ट शुल्क दरों पर निर्यात करते रहे। जब चीनी निर्यातकों के बीच समान प्रतिस्पर्द्धा है तो अलग-अलग पाटन मार्जिन का अभाव निर्यातों के अभाव के लिए उचित कारण नहीं हो सकता।
- xxiv. चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार निर्यातों और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों तथा निर्यातकों के आंकड़ों के अनुसार आयातों की तुलना यह दर्शाती है कि उत्तरदाता निर्यातक ने अन्य चीनी निर्यातकों की तुलना में कृत्रिम रूप से उच्चतर कीमत पर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है।
- xxv. (क) वर्तमान जांच से संबंधित किसी मुद्दे, (ख) नियम 22 के तहत शर्तें कैसे पूरी की जाती हैं; (ग) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए व्यावहारिक अनुरोधों के संबंध में कोई अनुरोध के संबंध में कोई तर्क नहीं दिए गए हैं।
- xxvi. मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। (क) "यह दर्शाने" के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि नियम 22 में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया गया है; (ख) यह दर्शाने के लिए कि निर्यातक के सामान्य मूल्य पर विचार किया जा सकता है, अपेक्षित सूचना नहीं दी गई है; (ग) निर्यातक द्वारा अधिकृत बिक्री दर्शाई जानी चाहिए।
- xxvii. आवेदक ने लिखित अनुरोधों में सजग रूप से कोई अनुरोध दायर नहीं किए हैं और अनुरोधों के गोपनीय रुपांतर में अथवा प्रत्युत्तर अनुरोधों में अपने सभी प्रमुख दावे दिए हैं, यह जानते हुए कि निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों तक पहुँचने योग्य प्रत्युत्तर बनाने की परिपाटी को नहीं अपनाते हैं। मौखिक रूप से किए गए किसी भी अनुरोध को केवल तभी ध्यान में लाया जाता है यदि वे लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया हो।
- xxviii. घरेलू उद्योग ने भारत को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। यह देखा जाएगा कि पाटन मार्जिन वस्तुतः मूल जांच की जांचावधि में निर्धारित पाटन मार्जिन से अधिक है।

13. आवेदक निर्यातक/उत्पादक द्वारा अनुरोध:

- i. आवेदक ने अप्रैल, 2014 से जून, 2015 की जांचावधि वाली निर्णायक समीक्षा जांच की जांचावधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया।
- ii. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि याचिका से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या आवेदक ने भारत को उत्पाद का निर्यात किया है अथवा नहीं। इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि हमने पहले ही प्राधिकारी को अपने आवेदन के साथ पूरी सूचना प्रस्तुत कर दी है। यह आवेदन पत्र से ही अपने आप स्पष्ट है कि आवेदक ने भारत को संबद्ध सामानों की काफी मात्रा का निर्यात किया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग का उपर्युक्त विवरण उनके लिखित अनुरोधों के अपने प्रस्तुतीकरण का विरोधाभासी है जिसमें उन्होंने खुद ही चीनी सीमा शुल्क और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार आवेदक की निर्यात कीमत दी है।
- iii. घरेलू उद्योग ने न्यू शिपर समीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र और प्रयोजन के संबंध में अनुरोध किया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि "यद्यपि किसी भी अधिकृत न्यू शिपर को अलग मार्जिन की मांग करने का अधिकार है, परंतु साथ ही निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि दावे अधिकृत हैं और पाटनरोधी शुल्क का कोई अनुचित प्रयोग/दुरुपयोग/प्रवंचना नहीं है। यह इसका कारण है कि आवेदक को यह दृढ़ता से सिद्ध करने की आवश्यकता है कि (क) वे सही/अधिकृत निर्यातक हैं जिन्होंने अधिकृत बिक्री की है, (ख) उन्होंने मूल जांच में सामानों का निर्यात नहीं किया है और (ग) वे संबद्ध सामानों के उस उत्पादक/निर्यातक से संबंधित नहीं है जिस पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है।"
- iv. आवेदक ने यह भी स्पष्ट किया कि वह ऐसे किसी देश में किसी भी कंपनी से संबंधित नहीं है जिस पर संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लागू हो। इस प्रकार, आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 की दोनों अपेक्षाओं को पूरा किया और न्यू शिपर समीक्षा की शुरुआत तथा अलग शुल्क दर के निर्धारण के लिए पात्र है।
- v. आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया। जिन दस्तावेजों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है, उन सब में व्यापारिक गोपनीय सूचना है और वे सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं हैं और इससे घरेलू उत्पादकों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता अथवा कोई पूर्वाग्रह नहीं होता।
- vi. यह कि संबंधित व्यापार सूचना (व्यापार सूचना संख्या 08/2018) 25.04.2018 को जारी की गई थी जबकि वर्तमान आवेदन पत्र आवेदक द्वारा उस तारीख से पूर्व दायर किया गया था। इस संबंध में, व्यापार सूचना में विशेष रूप से यह उल्लेख है कि यह उपर्युक्त व्यापार सूचना जारी करने के "बाद" दायर आवेदन पत्रों पर लागू है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे में कोई औचित्य नहीं है।
- vii. इस संदर्भ में, अनुरोध है कि उत्तरदाता घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित सभी अपेक्षाओं को भी पूरा करते हैं। वर्तमान जांच की शुरुआत उत्तरदाता द्वारा पर्याप्त रूप से यह सिद्ध करने के बाद की गई थी कि (क) वे सही/अधिकृत निर्यातक हैं, जिन्होंने अधिकृत बिक्री की है, (ख) उन्होंने मूल जांच में सामानों का निर्यात नहीं किया है और (ग) वे संबद्ध सामानों के उस उत्पादक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं हैं जिस पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है। प्राधिकारी ने आवेदन पत्र की पूर्णतः जांच की है और नियम 22 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अतिरिक्त सूचना मंगाते हुए पत्र जारी किया। अतः इस संबंध में घरेलू उद्योग के तर्कों को रद्द किए जाने की आवश्यकता है। उत्तरदाता प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे उत्तरदाताओं के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने की कृपा करें क्योंकि उन्होंने उत्तरदाताओं के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजन से सभी अपेक्षित सूचना दी है। उत्तरदाता प्राधिकारी से यह भी अनुरोध करते हैं कि कृपया वे उत्तरदाता के अधिकृत आशय के संबंध में तथा उसके द्वारा दायर आंकड़ों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए उनके द्वारा दायर आंकड़ों का स्थल सत्यापन करें।
- viii. घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित मामले के उद्घरण अब माननीय सेसटेट की टिप्पणी के संदर्भ में हैं जो एच एंड आर जॉनसन (इंडिया) लिमिटेड बनाम भारतीय संघ तथा अन्य [2008 (232) ई.एल.टी. 390] में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित पैराग्राफ में सेसटेट की टिप्पणी से अपनी नामजुरी व्यक्त की थी और नोट किया कि प्रथम बार के शिपर के मामले में पूर्ववर्ती अवधि नहीं दी जा सकती। इसके आधार पर, उच्च न्यायालय सहमत हुआ कि न्यू शिपर समीक्षा के संबंध में जांच की संभावित अवधि की अनुमति दी जानी चाहिए और इसे नकारा नहीं जा सकता। इसके मद्देनजर, इस संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क का औचित्य उनके उत्तरदायित्व अथवा कानूनी स्थिति के संदर्भ में नहीं बनता है तथा इसीलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।
- ix. यह पूर्व शर्त कि निर्यात वाणिज्यिक मात्रा में होने चाहिए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 के तहत अपेक्षा के विरुद्ध है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में यह उल्लेख है कि प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए न्यू शिपर समीक्षा करेंगे यदि (i) उत्पादक अथवा निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात न किया हो और (ii) वह उत्पादक अथवा निर्यातक उस निर्यातक देश में किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित न हो जो उत्पाद के संबंध में पाटनरोधी शुल्क के अध्वधीन है।

- x. यह कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित "वाणिज्यिक मात्राओं" की अपेक्षा से संबंधित निर्यातक पाटनरोधी शुल्क मिलाने के लिए अपनी कीमतें कृत्रिम रूप से कम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। वस्तुतः उत्तरदाता के लिए यह अरक्षणीय होगा कि वे उस समय भी निर्यातों की मात्रा अधिकतम करने के लिए प्रतिकूल कीमतों पर संबद्ध सामानों का निर्यात करें जब वे घरेलू उद्योग तथा अन्य चीनी उत्पादकों द्वारा पेश की गई कीमतों के विरुद्ध प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं जिनके सामानों पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है अथवा कम लागू है। उत्तरदाता अपनी मानक परिपाटी से विचलित नहीं हुए और भारत को जांच की अवधि के दौरान उस समय निर्यात किया जब वह बाजार मांग के अनुसार उपयुक्त कीमत प्राप्त करने में सक्षम था। इसके अतिरिक्त, एक उत्पादक द्वारा किए गए निर्यात से चीन से कुल निर्यातों की तुलना करना अनुपयुक्त तथा कानून के विरुद्ध होगा।
- xi. नियम 22 के तहत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि न्यू शिपर द्वारा निर्यात अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण की अनुमति देने के लिए खास न्यूनतम मात्रा का होना चाहिए। ऐसी अपेक्षा से संबंधित निर्यातक पर "वाणिज्यिक मात्राओं में निर्यात" का अतिरिक्त दायित्व बढ़ जाएगा जो अन्यथा नियम 22 में उल्लिखित नहीं है। दूसरे शब्दों में, निर्यातों की "प्रतिनिधिकारिता" की अपेक्षा रखकर प्राधिकारी ने एक शर्त लगाई है जो नियम 22 में नहीं दी गई है।
- xii. जूट उत्पादों के आयातों के संबंध में हाल ही में की गई न्यू शिपर समीक्षा जांच (फा. सं. 7/10/2017-डीजीएडी दिनांक 22.11.2018) में प्राधिकारी ने आवेदक निर्यातक मैसर्स जनता जूट मिल्स लि. को इस तथ्य के बावजूद अलग पाटन मार्जिन दिया कि संबंधित निर्यातक ने 50,000 मी. टन की कुल मांग में संबद्ध सामानों के केवल 23 मी. टन का निर्यात किया।
- xiii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित "वाणिज्यिक मात्राओं" की अपेक्षा से संबंधित निर्यातक पाटनरोधी शुल्क मिलाने के लिए अपनी कीमतें कृत्रिम रूप से कम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। वस्तुतः उत्तरदाता के लिए यह अरक्षणीय होगा कि वे उस समय भी निर्यातों की मात्रा अधिकतम करने के लिए प्रतिकूल कीमतों पर संबद्ध सामानों का निर्यात करें जब वे घरेलू उद्योग तथा अन्य चीनी उत्पादकों द्वारा पेश की गई कीमतों के विरुद्ध प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं जिनके सामानों पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है अथवा कम लागू है।
- xiv. घरेलू उद्योग का यह दावा है कि आयातकों से उत्तर का अभाव इस बात का साक्ष्य है कि उत्तरदाता ने किसी तरह इस तथ्य को छिपाने का प्रयास किया है कि कम अथवा नगण्य पाटन मार्जिन प्राप्त करने के लिए अवास्तविक कीमत पर टोकन निर्यात किया गया था और उसके बाद आक्रामक रूप से मात्रा का पाटन किया। इस संबंध में, यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग ने अपने सिद्धांतों और अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है और इस संबंध में कोई कानूनी अथवा वास्तविक अनुरोध नहीं किए हैं। अनुरोध है कि न तो उत्तरदाता और न ही प्राधिकारी स्वतंत्र आयातक को आगे चल रही जांच में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अतः इस प्रकार की प्रतिभागिता का अभाव किसी बात का साक्ष्य नहीं देता। घरेलू उद्योग के अनुरोध केवल अभियोगात्मक विवरण तथा अनुमान हैं जिनका कोई कानूनी अथवा वास्तविक औचित्य नहीं है। अतः हमारा प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इन अनुरोधों को रद्द करें।
- xv. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि आवेदक यह स्पष्ट नहीं करता कि किस आधार पर उन्होंने सामान्य मूल्य का दावा किया है। इस संबंध में, उत्तरदाता यह अनुरोध करते हैं कि प्राधिकारी की यह मानी गई परिपाटी है कि वे चीनी उत्पादकों के सामान्य मूल्य को स्वीकार न करें। यह तथ्य घरेलू उद्योग के लिखित अनुरोधों में भी अच्छी तरह दर्शाया गया है। अतः उत्तरदाता अनुरोध करते हैं कि प्राधिकारी भारत में उत्पादित संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर उत्तरदाता के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करें।
- xvi. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि संभावित जांच की अवधि वर्तमान मामले में औचित्यपूर्ण नहीं है और वे नहीं समझ सकते कि आवेदक ने भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात क्यों नहीं किया। इस संबंध में, आवेदक का अनुरोध है कि उत्तर में पैराग्राफ में घरेलू उद्योग का दावा भ्रामक और झूठा है। उत्तरदाता ने भारत को संबद्ध सामानों का 876.5 मी. टन निर्यात किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त विवरण उनके अपने अनुरोधों का विरोधाभासी भी है जिसमें उन्होंने खुद ही चीनी सीमा शुल्क और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार आवेदक की निर्यात कीमतें दी हैं। उत्तरदाता यह समझने में सक्षम नहीं हैं कि जब घरेलू उद्योग को अनुसार उत्तरदाता द्वारा कोई निर्यात नहीं है तो चीनी सीमा शुल्क और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार भारत में उनके निर्यात के लिए आवेदक की निर्यात कीमतें कैसे हो सकती हैं। स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग प्राधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है और इसीलिए उनके अनुरोध को पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए।
- xvii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि आवेदक की निर्यात कीमतें चीनी सीमा शुल्क और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार भारत को उनके निर्यात के लिए हैं। यद्यपि उत्तरदाता घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के दावे के कारण इस संबंध में कोई टिप्पणी देने से अलग रहा है, तथापि, उत्तरदाता का अनुरोध है कि उपर्युक्त आंकड़े पूर्णतः झूठे और निर्मित किए गए प्रतीत होते हैं। यह रिकार्ड का मामला है कि डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े किसी विशेष निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के आधार पर पृथक्करण नहीं करते। तथापि, घरेलू उद्योग ने उत्तर के तहत पैरा में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार उत्तरदाता की निर्यात कीमत देने का दावा किया है। स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े वास्तविक रूप से डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े नहीं हैं और घरेलू उद्योग डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के रूप में कुछ विनिर्मित आंकड़े प्रस्तुत कर प्राधिकारी को

भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। इसके मद्देनजर, उसके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों सहित घरेलू उद्योग के उपर्युक्त अनुरोध को सीधे-सीधे रद्द किया जाना चाहिए।

- xviii. यह कि वर्तमान मामले में वर्तमान जांच की शुरुआत उत्तरादाता द्वारा पर्याप्त रूप से यह सिद्ध करने के बाद की गई थी कि (क) वे सही/अधिकृत निर्यातक हैं, जिन्होंने अधिकृत विक्री की है, (ख) उन्होंने मूल जांच में सामानों का निर्यात नहीं किया है और (ग) वे संबद्ध सामानों के उस उत्पादक अथवा निर्यातक से संबंधित नहीं हैं जिस पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है। यह भी अनुरोध है कि सूचना दायर करने के बाद प्राधिकारी ने आवेदन पत्र की पूरी तरह से जांच की है और नियम 22 की अपेक्षा के अनुसार स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अतिरिक्त सूचना की मांग करते हुए पत्र जारी किया है। अतः घरेलू उद्योग का यह तर्क कि प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत करते समय उचित परिश्रम नहीं किया है, गलत है।
- xix. यह कि असंबद्ध आयातक की प्रतिभागिता का अभाव निर्यातक के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, चल रही जांच में प्रतिभागिता के लिए स्वतंत्र आयातक की गैर-प्रतिभागिता प्रतिभागी निर्यातकों के विरुद्ध नहीं मानी जा सकती। इस संदर्भ में घरेलू उद्योग के अनुरोध केवल अभियोगात्मक विवरण तथा अनुमान हैं जिनका कोई कानूनी अथवा वास्तविक औचित्य नहीं है। अतः आवेदक प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे घरेलू उद्योग के इन अनुरोधों को रद्द करें।
- xx. यह कि सामानों का निर्यात करने का निर्णय और ऐसे निर्यातों का चैनल पूरी तरह एक व्यापारिक निर्णय होता है जो पूर्णतः उत्पादक/निर्यातक पर होता है तथा आयातक की भुगतान नीतियों सहित विभिन्न कारकों पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, व्यापारियों के माध्यम से निर्यात करने के लिए कई देशों में बहुत सामान्य परिपाटी है।

14. आयातकों द्वारा अनुरोध

मैसर्स सदीप ऑर्गेनिक्स प्रा. लि. द्वारा दायर टिप्पणियां

- न्यू शिपर समीक्षा का दुरुपयोग हो सकता है।
- अलग निर्यातक की आवश्यकता क्या है जब उत्पादक सीधे ही निर्यात कर सकता है?
- निर्यातक और उत्पादक पर चीन के अन्य निर्यातकों तथा उत्पादकों की तरह वही पाटनरोधी शुल्क होना चाहिए।
- निर्यातक अन्य उत्पादों का भी निर्यात कर रहा है।
- उत्पादकों के पास सामग्री का पाटन करने की क्षमता है।
- इस एनएसआर से स्थानीय कीमतें कम होंगी और घरेलू उद्योग के लाभ को प्रभावित कर सकता है जिससे कि हानियां हो रही हैं।
- केंद्र सरकार अनंतिम पाटनरोधी शुल्क के लिए कहेगी और आयातक को समीक्षा के अंतिम जांच परिणाम के बाद वापसी के लिए आवेदन करना चाहिए।
- पाटनरोधी राशि बहुत अधिक है, अतः भारी पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए।

मैसर्स सुनीता कामर्शियल्स प्रा. लि. द्वारा दायर टिप्पणियां

- हम इस व्यापार में पिछले दो दशकों से अधिक समय से हैं। अलग-अलग चीनी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए मेलामाइन में कीमत का अंतर मुश्किल से 5-10 अमेरिकी डॉलर/मी. टन के घेरे में है। चीन में मेलामाइन का उत्पादन करने वाले 40 से अधिक संयंत्र हैं। चीन इस समय विभिन्न देशों को 3-4 लाख मी. टन प्रति वर्ष के घेरे में मेलामाइन का निर्यात करता है।
- भारत में मेलामाइन के आयातों का संलग्न विवरण यह दर्शाता है कि जिस कीमत पर आवेदक कंपनी ने उत्पाद का निर्यात किया है और जिस कीमत पर अन्य चीनी आपूर्तिकर्ताओं ने उत्पाद की आपूर्ति की है। यह देखा जाएगा कि जिस कीमत पर आवेदक कंपनी ने भारत को उत्पाद का निर्यात किया है और जिस कीमत पर अन्य चीनी आपूर्तिकर्ताओं ने भारतीय बाजार में उत्पाद की आपूर्ति की है, उस कीमत में 100-200 अमेरिकी डॉलर/मी. टन से अधिक का अंतर है।
- चूंकि हम खुदरा स्तर पर प्रचालन कर रहे हैं और उपभोक्ताओं के साथ व्यापक रूप से बातचीत कर रहे हैं, अतः हम उस कीमत से पूर्णतः अवगत हैं जिस पर आयातित उत्पाद बाजार में पुनः बेचा गया है। आवेदक कंपनी की कीमतों और बाजार में अन्य चीनी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लगाई गई कीमत में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। यह बात यह मानते हुए आश्चर्यजनक नहीं है कि भारतीय बाजार में पुनः बेचे गए चीनी मेलामाइन में विशिष्ट रूप से कोई खास अंतर है। यह तथ्य यह भी दर्शाता है कि आवेदक कंपनी द्वारा सूचित की गई निर्यात कीमत बनावटी है। केवल यह मानने अथवा दस्तावेज खुद में कीमत की विश्वसनीयता सिद्ध नहीं करते और इसीलिए केवल इस कारण कि आवेदक वाणिज्यिक ब्रीजक अथवा भुगतान का समय दिखा सकता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उत्पाद वस्तुतः इन कीमतों पर बेचा गया था। सीमित विक्री लेन-देनों में ये दस्तावेज बांछित दिशा में आसानी से तैयार किए जा सकते हैं।
- वर्तमान आवेदन पत्र अधिकृत नहीं है और नगण्य अथवा कम पाटनरोधी शुल्क की मांग करने का एक प्रयास है ताकि अन्य चीनी उत्पादकों द्वारा वर्तमान में लिए गए बाजार को इस कंपनी द्वारा आसानी से लिया जा सके। यहां तक कि यद्यपि आवेदक कंपनी

बहुत पुरानी स्थापित कंपनी है, तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मेलामाइन का उत्पादन करते हुए हाल ही में देखा है। यह देखते हुए कि चीन में काफी अधिशेष क्षमताएं हैं और चीनी उत्पादक बाजार प्राप्त करना कठिन बातें हैं, आवेदक स्पष्ट रूप से अन्य चीनी आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में भारतीय बाजार में अनुचित लाभ सृजित करने का प्रयास कर स्वयं के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास कर रहा है।

- v. यदि इस कंपनी को भेदभावपूर्ण तरीके से और अन्य चीनी आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में कम पाटनरोधी शुल्क दिया जाता है तो यह कंपनी वह बाजार आसानी से ले लेगी जिसकी पूर्ति अन्य चीनी उत्पादकों द्वारा की जा रही है। भारत में मेलामाइन की काफी कमी है और इसीलिए आयात की आवश्यकता होती है। गैर-चीनी स्रोतों से आयात कीमत चीनी स्रोतों की अपेक्षा काफी अधिक है। ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क के बाद भी देश में चीनी मेलामाइन का काफी आयात है। औसतन 35,000 मी. टन/प्रति वर्ष मेलामाइन नियमित रूप से चीन से आयात किया जा रहा है। अतः आवेदकों का अनुचित लाभ सृजित कर तैयार रूप में इस बाजार को लेने का इरादा है।
- vi. चूंकि हम देश में नियमित रूप से मेलामाइन का आयात और बिक्री कर रहे हैं, अतः हम आपको कुछ अन्य सूचना देना चाह रहे हैं जिसकी हमें यह सिद्ध करने में आवश्यकता हो सकती है कि कंपनी की कीमत कृत्रिम है।

आवेदक को अलग पाटन मार्जिन प्रदान करना

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में निम्नलिखित प्रावधान है :

"22. ऐसे निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन जिनकी मूल रूप से जांच नहीं की गई थी

(1) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत को उस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा करेंगे, बशर्ते ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह सिद्ध करते हैं कि वे निर्यातक देश के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से सम्बद्ध नहीं हैं, जिन पर उस उत्पाद हेतु पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार इस नियम के उप नियम (1) में यथा संदर्भित निर्यातकों अथवा उत्पादकों से किए गए आयातों पर जांच अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं करेगी।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अनंतिम आकलन करे और यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी संस्तुति करते हों तो आयातक से गारंटी प्राप्त करे और यदि ऐसी समीक्षा की परिणति ऐसे उत्पादों अथवा निर्यातकों के संबंध में पाटन के निर्धारण में होती हो, तो ऐसे मामलों में वह समीक्षा की शुरुआत की तारीख से, भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क अधिरोपित करेगी।"

16. विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.5 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

"9.5 यदि कोई उत्पाद आयातक सदस्य में पाटनरोधी शुल्क के अधीन हो तो प्राधिकारी जांच के अधीन निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक के लिए पाटन के अलग मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ तत्काल समीक्षा करेंगे जिसने जांच अवधि के दौरान आयातक सदस्य को उत्पाद का निर्यात नहीं किया हो बशर्ते कि ये निर्यातक या उत्पादक यह दर्शा सकत हो कि वे निर्यातक देश में ऐसे किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित नहीं हैं जो उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं। ऐसी कोई समीक्षा आयातक सदस्य में सामान्य शुल्क निर्धारण और समीक्षा कार्यवाही की तुलना में सक्रिय आधार पर शुरू की जाएगी और चलाई जाएगी। समीक्षा के दौरान ऐसे निर्यातकों या उत्पादकों से आयातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तथापि, प्राधिकारी मूल्यांकन को रोक सकते और/या यह सुनिश्चित करने के लिए गारंटी का अनुरोध कर सकते हैं कि यदि ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप ऐसे उत्पादकों या निर्यातकों के संबंध में पाटन का निर्धारण होता है तो पाटनरोधी शुल्क को समीक्षा की शुरुआत की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाया जा सके।"

17. उपर्युक्त नियमावली, डब्ल्यूटीओ करार में प्रावधानों और डीजीटीआर की विगत परिपाटी के अनुसार न्यू शिपर समीक्षा जांच पाटनरोधी शुल्क लगने वाले संबद्ध देश से किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक के संबंध में अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों के तहत की जानी होती है:

- i. यह कि निर्यातक अथवा उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात न किया हो।
- ii. यह कि निर्यातक अथवा उत्पादक यह दर्शाए कि वे उस निर्यातक देश में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध नहीं है जो संबंधित उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अध्याधीन हों।

18. वर्तमान मामले में मैसर्स कीटन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. (उत्पादक) और मैसर्स फोशान कैसीनो बिल्डिंग मैटेरियल कं. लि. (निर्यातक), चीन जन. गण. ने न्यू शिपर समीक्षा शुरू करने के लिए चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेलामाइन के आयातों पर अलग पाटन मार्जिन की मांग करते हुए प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया। जहां तक "एनएसआर" का दावा करने वाले उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों की पात्रता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने द्वितीय निर्णायक समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया था। प्राधिकारी ने द्वितीय निर्णायक समीक्षा में शुल्क मुक्त तथा शुल्क मुक्त श्रेणी से बाहर के अंतर्गत संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा और कीमत का सह-संबंध बनाने के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों का संदर्भ भी दिया है। प्राधिकारी ने पूर्व जांच में माने गए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से मूल जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के निर्यात न करने वाले आवेदक उत्पादक/निर्यातक के दावे का सह-संबंध बनाया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने एनएसआर के लिए आवेदक उत्पादक/निर्यातक द्वारा शर्त पूरी न करने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि उसने पूर्व में निर्यात किया है अथवा किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य द्वारा अन्य उत्पादक/निर्यातक के साथ उसके संबंध के बारे में साक्ष्य नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक वर्तमान मामले में न्यू शिपर समीक्षा की मांग करने के लिए पात्र हैं।

19. सामान्य मूल्य

- क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक उत्पादक/निर्यातक अर्थात् मैसर्स कीटन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. (उत्पादक) और मैसर्स फोशान कैसीनो बिल्डिंग मैटेरियल कं. लि. (निर्यातक), चीन जन. गण. ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है, परंतु बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली दायर नहीं की है। प्रत्युत्तर अनुरोधों में आवेदक ने दावा किया है कि चीनी उत्पादकों के सामान्य मूल्य को स्वीकार न करना प्राधिकारी की एक मानी गई परिपाटी है और अनुरोध किया है कि उत्पादक/निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य प्राधिकारी द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया जाए। तथापि, आवेदक ने पाटनरोधी नियमावली के पैरा 7 के पहले अथवा दूसरे परंतुक के संबंध में किसी भी विकल्प का सुझाव नहीं दिया है।
- ख. घरेलू उद्योग ने अपने प्रत्युत्तर अनुरोधों में यह अनुरोध किया है कि भारत में बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की निर्यात कीमत पर विचार किया जाए।
- ग. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माने गए देश के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 तथा 8 के अनुसार परिकलित किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान मामले में, आवेदक ने कोई एमईटी प्रश्नावली दायर नहीं की है और इसीलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के तहत विकल्प का पता लगाए जाने की आवश्यकता है। पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुक्रम निर्धारित है और उसमें यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा अन्य देशों में उस तीसरे देश से कीमत जिसमें भारत भी शामिल है, अथवा जहां यह संभव नहीं है, के आधार पर, अन्य किसी उपयुक्त आधार पर जिसमें उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत शामिल है, यदि आवश्यक हो तो विधिवत समायोजित करके, निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य अनुबंध 7 के तहत दिए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाने की अपेक्षा होती है।
- घ. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य निर्मित करने के संबंध में मौजूदा न्याय व्यवस्था मैसर्स शेनयांग मस्तुशिता एस. बैट्री कं. लि. बनाम मैसर्स एक्सआईड इंडस्ट्रीज लि. (सिविल अपील संख्या 6371/2003 दिनांक 23.02.2005) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, मैसर्स सेंच्युरी प्लाईवोर्ड्स (आई) लि. एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट याचिका सं. 6568/2017 दिनांक 04.10.2018) में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और मैसर्स अपोलो टायर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (अपील संख्या सी/768, 600, 601, 773, 769/2005-एडी दिनांक 09.09.2005) में सेसेटेड, प्रधान बेंच, नई दिल्ली में निहित है। इन निर्णयों में उपयुक्त विकल्प लेने तथा उससे जुड़े हुए दायित्वों के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देशों का प्रावधान है।
- ङ. पैरा 7 के पहले परंतुक के अनुप्रयोग पर विचार करने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही इसके लिए प्राधिकारी के पास कोई सामग्री उपलब्ध है। तथापि, जहां तक पैरा 7 में अगले परंतुक का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आयात मात्रा से संबंधित सूचना और चीन को छोड़कर अन्य देशों से संबद्ध सामानों की कीमतें डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों से उपलब्ध हैं। यह नोट किया जाता है कि यद्यपि चीन का जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के कुल आयातों का 30303 मी. टन, 44 प्रतिशत हिस्सा है। तथापि, अगली अधिकतम आयातों की मात्रा कतर से 16479 मी. टन की है जो 1450.48 डॉलर/मी. टन के औसत सीआईएफ पर 24.20 प्रतिशत का हिस्सा बनता है। जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और जापान से आयात क्रमशः 12 प्रतिशत (सीआईएफ 1530 डॉलर/मी. टन); 7 प्रतिशत (सीआईएफ 1532 डॉलर/मी. टन) और 3 प्रतिशत (सीआईएफ 1524 डॉलर/मी. टन) हैं।
- च. कतर एक गैर-संबद्ध देश होने के नाते, जिस पर कोई पाटनरोधी जांच नहीं चल रही है अथवा पाटनरोधी उपाय लागू नहीं है और कतर से आयात मात्रा काफी होने के नाते सीआईएफ कीमत भारत में देय कीमत की प्रतिनिधिकारक है। साथ ही, चूंकि चीन की आयात कीमत मौजूदा पाटनरोधी शुल्क से ठीक की जाती है, अतः कतर से आयात कीमत चीन से किसी पाटित कीमत द्वारा

प्रभावित नहीं होती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य निर्मित करने के लिए पैरा 7 का यह विकल्प समुचित है और संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य का प्रतिनिधिकारक है। सामान्य मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी समुद्री भाड़ा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत, समुद्री बीमा तथा बैंक प्रभारों जैसे विभिन्न तथ्यों पर उपयुक्त समायोजन मानदंडों को अपनाते हुए अपनी सतत परिपाटी के अनुसार समायोजन करेंगे, जैसा कि कारखानागत कीमत निकालने के लिए समान/सदृश्य स्थितियों में निरंतर किया जाता है। इसी को उत्पादक अर्थात् मैसर्स कीटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. की कारखानागत निर्यात कीमत के साथ पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के नियम 6(i) के अनुसार व्यापार के समान स्तर पर तुलना किए जाने का प्रस्ताव है। प्राधिकारी समुद्री भाड़ा (40 डॉलर/मी. टन), समुद्री बीमा (सीआईएफ का 0.5 प्रतिशत), अंतर्देशीय भाड़ा (एफओबी का 1 प्रतिशत), पत्तन सार-संभाल (एफओबी का 1 प्रतिशत), ऋण लागत/बैंक प्रभार (एफओबी का 1 प्रतिशत) की सीमा तक समायोजनों पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं। पैरा 7 के अनुसार विकल्पों के अनुक्रम में अगला उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए यदि आवश्यक हो तो विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत है जिसे प्राधिकारी विचार करने की आवश्यकता के लिए तभी नोट करते हैं यदि ऊपर उल्लिखित विकल्प उपलब्ध न हो।

- छ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार, तीसरे बाजार अर्थव्यवस्था के देश के चयन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को उपयुक्त अवसर दिया जाना होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चल रही एनएसआर जांच में मामले को पूरा करने के लिए समय-सीमा 2018 की रिट अपील संख्या 412 से 414 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर 30.06.2019 निर्धारित की गई है। निर्यातकों को 31.12.2018 तक एक वर्ष की संभावित जांच की अवधि प्रदान की गई थी। प्रश्नावली का उत्तर उत्पादक/निर्यातक द्वारा 08.02.2019 को दायर किया गया था। दिनांक 28.02.2019 के प्रत्युत्तर अनुरोधों में उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया कि प्राधिकारी चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्मित करने हेतु सिद्धांत भारत में उत्पादित संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करे जबकि घरेलू उद्योग ने भारत में बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की निर्यात कीमत का दावा किया। प्राधिकारी ने निर्यातक तथा उत्पादक द्वारा दायर आंकड़ों के सत्यापन के लिए आवेदक के प्रश्नावली के उत्तर का डेस्क अध्ययन किया। प्राधिकारी मानते हैं कि एनएसआर जांच के मामले में, जिसमें एक वर्ष की संभावित अवधि का प्रावधान है, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विकल्प का उत्तर देने का समय ऊपर उल्लिखितानुसार 30.06.2019 की पूर्णता की तारीख के मामले में पूर्णतः उपयुक्त है। निर्यातक, घरेलू उद्योग और दो आयातकों द्वारा प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों को प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों और जांच के तहत बाद के पैराओं में लिया गया है।

उत्पादक, निर्यातक अर्थात् मैसर्स कीटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि. (उत्पादक) और मैसर्स फोशान कैसीनो बिल्डिंग मैटेरियल कं. लि. (निर्यातक) का प्रतिनिधित्व करने वाली एएसएल

निर्यात कीमत

20. जांच की अवधि के दौरान आवेदक उत्पादक (मैसर्स कीटुन जिनजियांग केमिकल इंडस्ट्री कं. लि.) ने निर्यातक मैसर्स फोशान कैसीनो बिल्डिंग मैटेरियल कं. लि. को 12 लेन-देनों के माध्यम से संबद्ध सामानों की *** डॉलर/मी. टन की कीमत पर *** मी. टन कारखानागत आधार पर बिक्री की है। उसके बाद मैसर्स फोशान कैसीनो बिल्डिंग मैटेरियल कं. लि. ने भारत में मैसर्स एक्जिम इनकारपोरेशन और मैसर्स संजय केमिकल्स को क्रमशः *** मी. टन और *** मी. टन की सीमा तक उसी मात्रा में निर्यात किया है। भारत में निर्यातक मैसर्स फोशान कैसीनो बिल्डिंग मैटेरियल कं. लि. को उत्पादक की कारखानागत बिक्री कीमत वेट को हटाकर *** डॉलर/मी. टन के रूप में दावा किया गया है।

21. उपर्युक्त कारखानागत कीमत के समर्थन में उत्पादक ने निर्यातक और संबद्ध बैंक प्रमाण-पत्र को अपने बिक्री बीजक प्रदान किए हैं। उत्पादक द्वारा दायर प्रश्नावली के परिशिष्ट 3 ग में उत्पादक ने मैसर्स फोशान कैसीनो बिल्डिंग मैटेरियल कं. लि. को बिक्री कीमत का उल्लेख किया है और अंतर्देशीय भाड़े का भी उल्लेख किया है। डेस्क सत्यापन के दौरान उत्पादक ने स्पष्ट किया कि मैसर्स फोशान को उनके द्वारा दिया गया बीजक कारखानागत आधार पर है और भंडारण खुद उठाने के आधार पर सुपुर्दगी शर्त दर्शाते हुए निर्यातक के साथ अपनी बिक्री संविदा प्रदान की है। अतः प्राधिकारी *** डॉलर/मी. टन पर अंतर्देशीय भाड़ा पर कोई समायोजन न करते हुए केवल नेट वेट पर निर्यातक को उत्पादक की कारखानागत बिक्री का संदर्भ देने का प्रस्ताव करते हैं।

22. निर्यातक ने (*** डॉलर/मी. टन) की कीमत पर कारखानागत आधार पर ऊपर उल्लिखितानुसार दो आयातकों को इन संबद्ध सामानों की बिक्री की है। उपर्युक्त आंकड़ों के समर्थन में निर्यातक ने आयातकों को निर्यातक के बीजक, निर्यातक द्वारा प्राप्त भुगतान, संबद्ध सामानों की खरीद और पुनः बिक्री कीमत दर्शाते हुए दो आयातकों के लेजर प्रदान किए हैं। तथापि, मैसर्स एएसएल द्वारा प्रविष्टियों का कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है जिन्होंने आवेदक की प्रश्नावली के लिए किए गए डेस्क अध्ययन के अनुक्रम में दिनांक 29.04.2019 के पत्र द्वारा आयातकों से संबंधित कुछ आंकड़े दायर किए। निर्यातक ने बैंक प्रभारों के संबंध में समायोजन का दावा किया है। इसके अतिरिक्त निर्यातक ने अपने प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 9 में दावा किया है कि भारत में उपभोक्ताओं को इन संबद्ध सामानों की बिक्री लाभ पर है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने यद्यपि कैलेंडर वर्ष 2016 और 2017 में समग्र हानि का दावा किया है, तथापि, उसने जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के लिए भी समग्र आधार पर लाभप्रदता का दावा किया है। गैर-विचाराधीन उत्पाद का जांच की अवधि के दौरान हानि पर बिक्री होने का दावा किया गया है।

निर्यातक ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर में परिशिष्ट 1 में भारत को 2017 में भी संबद्ध सामानों की कुछ मात्रा के निर्यातों का दावा किया है। तथापि, निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान और भारत को छोड़कर किसी अन्य देश को पूर्व तीन वर्षों के दौरान संबद्ध सामानों की बिक्री नहीं की है।

2017 में और बिक्री लागत, बिक्री मूल्य और लाभप्रदता के मानदंडों के संबंध में जांच की अवधि में भारत को संबद्ध सामानों के निर्यातों की जांच करने पर यह नोट किया जाता है कि निर्यातक द्वारा दावा की गई बिक्री लागत 2017 की तुलना में जांच की अवधि में 3 प्रतिशत तक कम हुई जबकि बिक्री कीमत 13 प्रतिशत तक बढ़ी और प्रति यूनिट लाभ लगभग 200 प्रतिशत तक बढ़ा। जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री के संबंध में निर्यातक की लाभप्रदता के मद्देनजर ऊपर बताए गए अनुसार निर्यातक को उत्पादक की कारखानागत कीमत उचित मानी जाती है और उसे कारखानागत निर्यात कीमत के रूप में अपनाया गया है। निर्यातक की प्रकटन पश्चात टिप्पणियों को प्रकटन पश्चात टिप्पणी और जांच पैराओं में बाद में लिया गया है।

आवेदक उत्पादक/निर्यातक की निर्यात कीमत और मात्रा की प्रतिनिधिकारिता

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और आयातकों, दोनों में आवेदक न्यू शिपर द्वारा भारत में संबद्ध सामानों की निर्यात मात्रा और कीमत की प्रतिनिधिकारिता और उपयुक्तता के संबंध में मुद्दे उठाए हैं। प्राधिकारी उपर्युक्त दावों का खंडन करते हुए और संगत पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों का हवाला देते हुए तथा विद्यमान कीमत पर उनके द्वारा किए गए निर्यातों को देखते हुए आवेदक न्यू शिपर द्वारा किए गए अनुरोधों को भी नोट करते हैं।

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएस और डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि के दौरान चीन से संबद्ध सामानों के कुल आयात पुष्टि करते हैं और क्रमशः 30303 मी. टन तथा 30278 मी. टन हैं। आवेदक न्यू शिपर द्वारा *** मी. टन के निर्यात जांच की अवधि के दौरान चीन से कुल आयातों का 2-3 प्रतिशत हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आवेदक उत्पादक/निर्यातक के संबद्ध सामानों की सीआईएफ कीमत चीन से संबद्ध सामानों की औसत कीमत की तुलना में काफी अधिक हैं। यद्यपि, आवेदक उत्पादक/निर्यातक की अपेक्षा अधिक कीमत पर बहुत कम आयात लेन-देन ही हैं। तथापि, ये आवेदक उत्पादक/निर्यातक से कम मात्रा के हैं और साथ ही इनमें से कुछ लेन-देन शुल्क मुक्त स्कीम के तहत हैं।

25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि द्वितीय निर्णायक समीक्षा में आयातकों द्वारा सहारा लिए जा रहे अधिक बीजक के मुद्दे को डीआरआई द्वारा दिए गए आंकड़ों वाली आयात कीमत, शुल्क मुक्त श्रेणी के तहत आयात कीमतों तथा जांच के दौरान प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई चीनी सीमा शुल्क निर्यात कीमतों से सह-संबंध बनाकर उपयुक्त रूप से जांच परिणाम में हल किया गया था।

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने न्यू शिपर द्वारा निर्यातों की मात्रा की समुचितता तथा उसकी उपयुक्तता के संबंध में अपने अनुरोधों में अन्य देशों के अधिनियम में प्रावधानों का उल्लेख किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि भारत की पाटनरोधी नियमावली वाणिज्यिक मात्राओं की किसी दहलीज को निर्धारित नहीं करती। इसके अतिरिक्त, उनकी निर्यात कीमत की उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए यद्यपि उन्होंने अनुरोध किया है कि किसी स्वतंत्र आयातक की प्रतिभागिता पर जोर नहीं दिया जा सकता, तथापि, बाद में यह सिद्ध करने के लिए आयातकों द्वारा संबद्ध सामानों की खरीद और बिक्री के लेजर आंकड़े प्रदान किए कि पुनः बिक्री कीमत मूल्य वृद्धि के साथ है। तथापि, आयात लेन-देनों की प्रविष्टियों का बिल तथा निर्धारित प्रश्नावली उत्तर नहीं दिए गए हैं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल्य वृद्धि के साथ होने के नाते आयातक द्वारा बिक्री के संबंध में आवेदक के दावे को न्यू शिपर के लिए अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण होने तक के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है जिसकी न्यू शिपर समीक्षा पूर्ण होने के बाद आयातक द्वारा पाटनरोधी शुल्क देने की देयता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि न्यू शिपर को अलग पाटन मार्जिन देने के लिए प्राधिकारी को सामान्य मूल्य और निर्यातगत कीमत, दोनों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक न्यू शिपर ने न्यू शिपर को अलग पाटन मार्जिन देने के जनता जूट मिल के मामले में किए गए एनएसआर का उल्लेख किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसी प्रकार के निर्धारण में प्राधिकारी ने निर्यात कीमत की उपयुक्तता और विश्वसनीयता सिद्ध करने की आवश्यकता पर जोर दिया था और मामले के तथ्यों पर रहते हुए आवेदक को गैर-नमूनाकृत श्रेणी का पाटनरोधी शुल्क ही देने का निर्णय लिया था।

27. प्रकटन में उत्तर में किए गए इस पहलू के संबंध में अनुरोध बाद के पैराओं में लिए गए हैं।

ड हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार, प्राधिकारी ने 22 मई, 2019 को जारी प्रकटन विवरण द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को वर्तमान जांच के अनिवार्य तथ्य प्रकट किए और उन्हें सलाह दी कि वे 03 जून, 2019 तक उन पर अपनी टिप्पणियां दायर करें। बाद में यह तारीख उन आवेदकों के अनुरोध पर 07 जून, 2019 तक बढ़ाई गई थी जिन्होंने प्रकटन विवरण के अन्य पहलुओं के अलावा प्रतिनिधि देश की इच्छा पर टिप्पणियां दायर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। आवेदक और घरेलू उद्योग से प्राप्त टिप्पणियों को संगत समझी गई सीमा तक वर्तमान जांच परिणाम में हल कर दिया गया है।

28. (i) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- क. आयातक द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय रूपांतर घरेलू उद्योग को उपलब्ध नहीं है। यह केवल प्रकटन विवरण के माध्यम से ही था कि घरेलू उद्योग दिनांक 29.04.2019 के पत्र के माध्यम से दायर सूचना के संबंध में जान पाया।
- ख. जांच की संभावित अवधि के कारण आवेदक उच्चतर कीमतों पर भारत में निर्यात कर याचिका में छेड़छाड़ करने और अपने ढंग से बनाने में सक्षम हो पाया है।
- ग. गौण सूत्रों के अनुसार आयात आंकड़े यह दर्शाते हैं कि आवेदकों से सामग्री आयात करने वाले दो आयातकों ने अन्य की अपेक्षा उच्चतर कीमतों पर आयात किया है।
- घ. सभी आयातकों, जिनके पास आवेदकों से तुलनीय मात्रा थी और कम मात्रा पर भी थी, ने बहुत कम कीमतों पर उत्पाद का आयात किया है।
- ङ. जिन उत्पादकों के पास उच्चतर कीमत है, केवल वे उत्पादक हैं- (क) एरोन यूनिवर्सल (पिगमेंट्स में प्रयुक्त विशेषीकृत उत्पाद); (ख) नोबल लेमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड; (ग) सुमिलोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड; (घ) हाई-टेक एग्रो मिल्स (सभी ने प्रत्येक ने चीन से लगभग 22 मी. टन अथवा कुल आयात का 0.1 प्रतिशत आयात किया है; अग्रिम लाइसेंस के तहत माना जाता है)।
- च. चीन सीमा शुल्क के आंकड़े दर्शाते हैं कि आवेदक ने अन्य की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से उच्चतर कीमतों पर भारत को उत्पाद का निर्यात किया है।
- छ. निर्यातक द्वारा दायर उत्तर से यह भी सिद्ध है (प्रकटन विवरण में उल्लिखितानुसार) जिसमें उन्होंने जांच की अवधि के दौरान किए गए लदान में 200 प्रतिशत तक का लाभ बढ़ाया है। यह समझ में नहीं आता कि जब लागत में 3 प्रतिशत तक गिरावट आई है तो निर्यातक अपनी बिक्री कीमत 13 प्रतिशत तक बढ़ाने में सक्षम था जिससे विगत की अपेक्षा 200 प्रतिशत उच्चतर लाभ अर्जित हुआ।
- ज. यह मामला पूरी तरह से बनाया हुआ है, जैसा कि रिकार्ड में साक्ष्य से देखा जा सकता है।
- झ. संबंधित उत्पादक चीन में नया उत्पादक नहीं है। उसकी स्थापना 12 सितंबर, 2008 को की गई थी और संबंधित व्यापारी टाइलों की बिक्री में काम करता है और उसे एक नए बाजार की पूर्ति करने के लिए बिना किसी अनुभव के महत्वपूर्ण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाले उत्पाद के लिए लिया गया है।
- ञ. संबंधित आयातक रातों रात आयातक बनने वाले भी हैं जिनके पास मेलामाइन में व्यापार करने अथवा उससे संबंधित कार्य करने का विगत अनुभव नहीं है।
- ट. आयातक ने जांच की शुरुआत के स्तर पर प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया और जांच में उसकी कोई रुचि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुनवाई के बाद कुछ आंतरिक संवेदनशील दस्तावेज चीनी निर्यातक के कानूनी परामर्शदाता को चुनिंदा रूप से दिए गए थे और आयातक की ओर से दायर किए गए थे।
- ठ. भारत में मेलामाइन की बिक्री करने का अनुभव न रखने वाले कुछ नए उत्पादक और निर्यातक बाजार की अपेक्षा अधिक उच्चतर कीमत दे रहे हैं जिसमें वे 200 प्रतिशत का लाभ बना रहे हैं और जो कम कीमत प्राप्त करने वाले नए व्यापारी के विरुद्ध 150 अमेरिकी डॉलर पर है।
- ड. आयातक के गोपनीय आंकड़े दायर करने वाला निर्यातक का प्रतिनिधि निर्यातक और आयातक के बीच एक प्रतिपूरक व्यवस्था दर्शाता है और इसीलिए इन कीमतों पर ध्यान न दिए जाने की आवश्यकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी और सेसटेट के कुम्हो निर्णय पर विश्वास किया जाता है।
- ढ. आवेदक के दावे कई स्तरों पर प्राधिकारी की परिपाटी और कानून से पूर्णतः भिन्न हैं, विशेष रूप से दावे सिद्ध करने के दायित्व के संबंध में। आवेदक द्वारा किए गए दावों में कोई औचित्य नहीं है जब तक कि साक्ष्य द्वारा सिद्ध न हो और उन्हें अन्यथा सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग के विरुद्ध न हो।
- ण. आवेदक द्वारा किए गए निर्यात भारत में चीन से कुल आयातों का केवल 2-3 प्रतिशत है जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये लेन-देन बनाए गए हैं।
- त. निर्यातक ने दायर प्रश्नावली के उत्तर में दावा किए गए खर्चों, आधार और बिक्री की शर्तों सहित सूचना पूर्णतः और इरादतन छिपाई है।
- थ. आयातक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, परंतु केवल अनियमित रूप से प्राधिकारी की परिपाटी और कानून की पूर्णतः उपेक्षा कर अपनी सुविधा के अनुसार सूचना दायर की है। उपर्युक्त सूचना सार्वजनिक पहल में भी उपलब्ध नहीं है।

- द. डीआरआई ने जांच का निष्कर्ष निकालने के बाद यह पाया कि एक्जिम कॉर्प्स सहित आयातक पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए उत्पाद की मरम्मत कर रहे थे। इससे इन आयातकों की आयात कीमत की विश्वसनीयता और साख पर गंभीर प्रश्न उठता है।
- ध. आवेदक ने यह मानते हुए सामान्य मूल्य के लिए किसी दावे अथवा साक्ष्य के बिना अलग पाटन मार्जिन के लिए दायर किया है कि प्राधिकारी उसके लिए प्रयास करेंगे।
- न. निर्यातक द्वारा एमईटी के लिए कोई स्पष्टीकरण अथवा दावा नहीं दिया गया है जिससे अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण और जटिल हो गया है। प्राधिकारी अर्द्ध-न्यायिक होने के नाते कानून के अनुसार नियम 7 के तहत सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए खुद श्रम नहीं कर सकता।
- प. घरेलू उद्योग का आवेदक के बचाव के लिए आने का और सामान्य मूल्य के निर्धारण से संगत सूचना प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं है।
- फ. चूंकि, आवेदक ने अलग शुल्क मार्जिन के लिए अनुरोध किया है, अतः संगत साक्ष्य तथा सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की समर्थक सूचना के साथ सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संगत सूचना प्रदान करना आवेदक का दायित्व है।
- ब. अपने दायित्वों के निर्वहन में आवेदक ने अपने प्रत्युत्तर अनुरोधों में घरेलू उद्योग के तर्कों का उत्तर देते समय केवल यह उल्लेख किया है कि सामान्य मूल्य उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- भ. यह जांच के इस स्तर पर अत्यधिक देरी का मामला है जिसमें प्राधिकारी जांच की शुरुआत के चरण में पीछे जाएगा और घरेलू उद्योग से संगत सूचना मंगाएगा।
- म. सामान्य मूल्य के संबंध में कोई सूचना प्रदान न कर निर्यातक एक तरह से वर्तमान जांच में असहयोगी हो गए हैं और प्राधिकारी के लिए कोई अलग शुल्क दिए बिना जांच में रद्द करना अपेक्षित है।
- य. निर्दिष्ट प्राधिकारी का सामान्य मूल्य के साक्ष्य एकत्रित करने का कोई दायित्व नहीं है तथा आवेदक ने कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया कि वह अपने आंकड़ों/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा नहीं कर रहा था। अतः प्राधिकारी यह मानते हुए जांचों को रद्द भी कर सकते हैं कि पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए रिकार्ड में अपर्याप्त सूचना एवं साक्ष्य हैं।
- कक. प्राधिकारी का सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्णय करने का दायित्व है, यहां तक कि जहां हितबद्ध पक्षकार द्वारा साक्ष्य दिए गए हैं, यदि हितबद्ध पक्षकार एक उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करते अथवा इंकार करते हैं अथवा जांच में काफी बाधा डालते हैं। तथापि, अविश्वसनीय सूत्रों से सूचना के प्रयोग से बचने के लिए आयातक देशों के प्राधिकारियों द्वारा सभी उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए (डब्ल्यूटी मिश्र-स्टील रिबार)।
- खख. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के संबंध में किसी सूचना के अभाव में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार भारत में कतर आयात कीमत पर विश्वास किया है।
- गग. डीजीसीआईएस के आंकड़े विश्वसनीय सूचना है और उसका निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सतत् रूप से प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही, इसके विपरीत कोई साक्ष्य नहीं रहा है।
- घघ. उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना कतर से निर्यात कीमत का प्रयोग सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए वर्तमान मामले में तथ्यों और परिस्थितियों में अनुपयुक्त नहीं हैं।
- डड. पैरा 7 में उल्लिखित अनुक्रम के अनुसार, सामान्य मूल्य भारत सहित अन्य देशों को तीसरे देश से कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा क्योंकि आवेदक द्वारा उपयुक्त तीसरे देश में निर्मित सामान्य मूल्य के लिए कोई भी सूचना नहीं दी गई है।
- चच. उपयुक्त तीसरा देश निर्धारित करने के लिए यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, मैक्सिको और ब्राजील द्वारा लागू की गई परिपाटियों की तुलना प्रयुक्त निम्नलिखित व्यापक कारकों को दर्शाती है – (क) सदृश देश से विनिर्माण में निर्यात का माप, (ख) सदृश देश से आयातों की मात्रा, (ग) विकास का स्तर, संबंधित आर्थिक एवं संबंधित उत्पाद, (घ) सदृश देश में उत्पादित उत्पाद, (ङ) विनिर्माण प्रक्रिया, (च) बाजार का खुलापन, (छ) उत्पादों में समानता।
- छछ. यह नहीं कहा जा सकता कि कतर वर्तमान मामले में एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश नहीं है। वस्तुतः कतर सबसे अधिक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।
- जज. कतर विश्व में संबद्ध सामानों का एक सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है और केवल चीन जन. गण. के नीचे भारत को संबद्ध सामानों का दूसरा सबसे अधिक निर्यातक देश है।
- झझ. कतर में उत्पादित संबद्ध सामान इन सामानों के समान उत्पाद हैं और विनिर्माण प्रक्रिया चीन जन. गण. में और भारत में उत्पादकों की एक समान है।

- जज. इसके अतिरिक्त, कतर संबंधित उत्पाद के विकास के स्तर और अर्थव्यवस्था के स्तर के संदर्भ में चीन जन. गण. से तुलनीय है तथा संबंधित उत्पाद के लिए उत्पादन, बिक्री एवं निर्यात के लिए बाजार कतर में खुला है तथा किसी अन्य गैर बाजार बल से मुक्त है।
- टट. घरेलू उद्योग को भारत में जर्मनी, जापान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अन्य देशों से आयात कीमतें देने में कोई आशंका नहीं है क्योंकि इन देशों से आयात कीमत कतर से अधिक है।
- ठठ. (क) विचाराधीन उत्पाद के विकास के स्तर, (ख) उत्पादन प्रक्रिया, (ग) विनिर्माण का माप, (घ) कच्ची सामग्री उपलब्धता जैसे कारकों पर उस समय जोर दिया जाता है जब सामान्य मूल्य घरेलू कीमत पर आधारित है, अतः बाजार और कीमत की तुलनीयता बहुत महत्वपूर्ण होती है।
- डड. संगत मानदंड जब सामान्य मूल्य भारत में तीसरे देश से कीमत के आधार पर हैं तो निर्यात की मात्रा होते हैं और यह तथ्य कि तीसरा देश पाटन जांच के अध्यक्षीन न हो, संबद्ध देश और सदृश देश की बाजार तुलनीयता महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अपनाई गई कीमत भारत में निर्यात कीमत है। अतः भारतीय बाजार भी संगत है।
- ढढ. जब बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध न हो तो क्या भारत सहित अन्य देशों में बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से कीमत पर विचार किया जा सकता है। यदि नहीं तो भारत में लागत अथवा कीमत पर विचार किया जा सकता है।
- णण. नियम 7 के तहत, स्पष्ट अनुक्रम उल्लिखित किया गया है। इस प्रकार, कानून के तहत अनुक्रम को पूरा किए बिना सामान्य मूल्य के लिए किसी सिद्धांत पर विचार करना अनुमत्य नहीं है।
- तत. आवेदक ने यह तर्क नहीं दिया है कि कतर की कीमत कैसे उपयुक्त नहीं है और उसे भारत में निर्यात कीमत के लिए क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिए। यह देश साधारण व्यापार प्रक्रिया में कार्य करता है।
- थथ. जांच की अवधि सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए पूरी स्वच्छता वाली है। जांच की अवधि ही इस मामले में निर्धारित नहीं की गई है बल्कि प्राधिकारी जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए कुछ आंकड़ों/सूचना पर विचार करने से बाधित हुए हैं।
- दद. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के निर्णय को सेसटेट में चुनौती दी गई थी और उस निर्णय को थाई एक्रिलिक फाइबर के. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में पलटा गया था।
- धध. सामान्य मूल्य के लिए भारत में लागत के प्रयोग हेतु आवेदक का दावा अत्यधिक देरी से हुआ है और ऐसा दावा जांच के इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- नन. इसके अतिरिक्त, भारत में लागत से संबंधित सूचना और आंकड़े जांच की अवधि के लिए प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं हैं और जांच में दिए गए स्तर पर रिकार्ड में कोई नई सूचना नहीं लाई जा सकती।
- पप. आवेदक का व्यवहार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए कोई सूचना देने का इरादा नहीं दर्शाता। इसके बजाए, यह विश्वास दर्शाता है कि प्राधिकारी को ही ऐसी सूचना के लिए प्रयास करना चाहिए।
- फफ. साथ ही, इस स्तर पर निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग से सामान्य मूल्य के निर्धारण से संबंधित सूचना देने के लिए नहीं कह सकते।
- बब. प्राधिकारी ने पहले ही प्रकटन विवरण जारी कर दिया है और घरेलू उद्योग द्वारा उसी कार्यप्रणाली की तैयारी के साथ नई सूचना का अनुरोध करना और उसके बाद विश्लेषण तथा कानून की उचित प्रक्रिया करने से जांच में कम से कम अगले तीन माह और लग जाएंगे।
- भभ. चूंकि, जांच की अवधि गैर वित्तीय वर्ष है, अतः संगत सूचना सार्वजनिक पटल पर भी उपलब्ध नहीं है।
- मम. साथ ही, कच्ची सामग्री में कुल लागत का केवल 45 प्रतिशत होता है, अतः केवल कच्ची सामग्री का सूचकांक निर्धारण के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

(II) एनएसआर आवेदकों द्वारा किए गए अनुरोध

- क. प्रकटन विवरण प्राधिकारी द्वारा प्रथम पत्राचार है कि कतर चीन के लिए तीसरा बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाएगा। विकास के अनिवार्य स्तर पर कोई ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।
- ख. पैरा 7 में विकास का स्तर का प्रावधान है, उसे विश्वसनीय सूचना के आधार पर ध्यान में रखा जाए। प्राधिकारी ने ऐसे चयन के लिए भारत में कतर से आयातों की मात्रा पर विश्वास किया है जो अनुपयुक्त है।
- ग. कतर एक प्रतिनिधि तीसरे बाजार वाली अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में पैरा 7 में दृष्टिकोण के विरुद्ध है और आवेदकों के प्रति भेदभावपूर्ण है।

- घ. कतर को एक प्रतिनिधि देश के रूप में प्रस्तावित चयन के संबंध में रिकार्ड में कोई संगत सूचना अथवा साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- ङ. यह प्रकट किया गया है कि क्या घरेलू बिक्री अथवा तीसरे देश की निर्यात बिक्री तथा कतर में उत्पादन लागत संबंधी पूर्ण आंकड़े रिकार्ड में हैं।
- च. ऐसी सूचना तीसरे देश के निर्यातों अथवा कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित करने के लिए विगत मामलों में प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से मांगी गई है।
- छ. वर्तमान मामले में ऐसी कोई सूचना/आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और न ही घरेलू उद्योग द्वारा अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सुझाए गए तीसरे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से संगत सूचना प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किया गया है।
- ज. ऐसी स्थिति में प्राधिकारी का कतर को एक प्रतिनिधि देश के रूप में लेना कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है अथवा न ही समान मामलों में अपनाए गए उनके अपने दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- झ. विगत जांचों में तीसरे देशों के डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़े प्राधिकारी के पास मौजूद थे। तथापि, प्राधिकारी ने तीसरे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश की निर्यात कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों को उपयुक्त नहीं माना।
- ञ. एनएसआर जांच में सामान्य मूल्य के परिकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका इसी प्रकार के मामले में प्राधिकारी द्वारा की गई निर्णायक समीक्षा जांचों में तथा मूल जांचों में प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए सिद्धांत को अपनाना है। किसी अन्य सिद्धांत को अपनाने से निर्यातकों के लिए दो अलग-अलग सामान्य मूल्य बनेंगे जो प्रकृति में भेदभावपूर्ण होगा।
- ट. घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा मामले में उल्लेख किया कि सामान्य मूल्य इस कारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- ठ. चूंकि, प्राधिकारी का मत कतर को एक प्रतिनिधि देश के रूप में लेने का था और इसके लिए रिकार्ड में पर्याप्त साक्ष्य हैं, अतः उसकी संगतता तथा पर्याप्तता दर्शाने के लिए सबूतों का भार प्राधिकारी पर है। उस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है और ऐसे आंकड़ों एवं सूचना के अभाव में आवेदक और कोई टिप्पणी देने में असमर्थ है।
- ड. आवेदकों ने घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर अनुरोधों के लिए अनुरोध किया। तथापि, प्राधिकारी ने विगत परिपाटी का उल्लेख करते हुए उसे बताने से इंकार कर दिया। प्रत्युत्तर में निहित सूचना इस मामले की विशेष महत्ता की है क्योंकि उसे कतर को एक उपयुक्त तीसरे देश के रूप में चुने जाने के लिए प्रयुक्त किया गया है।
- ढ. चूंकि, अनुरोध बताए नहीं गए हैं, अतः आवेदक प्रभावी और उपयुक्त तरीके से अपनी टिप्पणियां देने की स्थिति में नहीं हैं।
- ण. कतर के विकास का स्तर चीन के विकास के स्तर से तुलनीय नहीं है। किसी देश के विकास का स्तर जीडीपी प्रति व्यक्ति, मानव विकास सूचकांक आदि जैसे कारकों के संबंध में यूएनडीपी, विश्व बैंक, आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मापा जाता है। प्राधिकारी विश्व भर में तुलना के लिए ऐसे कारकों का प्रयोग करते हैं। तथापि, प्रकटन विवरण में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिसका प्रयोग किया गया हो।
- त. प्रकटन विवरण दो देशों और उनकी तुलनीय में उद्योग के विकास के स्तर के संबंध में मौन है।
- थ. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के प्रस्तावित चयन और अपनाई गई प्रक्रिया शेनयांग मत्सुशिता एस. बैट्री कं. लि. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा टिप्पणियों के पूर्णतः विरोधाभास में है।
- द. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्रतिनिधि देश का चयन जांच की शुरुआत में ही अपनाए जाने की प्रक्रिया है। प्राधिकारी ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के लिए अधिदेशित अन्य प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया है।
- ध. साधारण व्यापार प्रक्रिया और समीपस्थ लेन-देनों के संबंध में निर्धारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक ऐसे प्रतिनिधि देश के संबंध में पूर्ण तथा विस्तृत आंकड़े/सूचना रिकार्ड में और प्राधिकारी के पास न हो।
- न. कतर को एक प्रतिनिधि देश के रूप में देने के मुद्दे के संबंध में आवेदकों को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। आवेदक को सुनने का अधिकार न देने के लिए समय का अभाव कारण नहीं हो सकता।
- प. एनएसआर जांचों की सूची का अवलोकन यह दर्शाता है कि प्राधिकारी ने आवेदकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन गैर बाजार अर्थव्यवस्था से उनकी लागत एवं अन्य के आधार पर किया है। प्राधिकारी की इस सुस्थापित परिपाटी से विचलन और असमानता के आधार पर तथा कानून के समान संरक्षण के आधार पर विचलन का कोई कारण नहीं है।
- फ. संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारी प्रतिनिधि देश के चयन के लिए आर्थिक तुलनीयता का मूल्यांकन करते हैं और ऑस्ट्रेलियाई पाटनरोधी पुस्तिका में उचित प्रतिनिधि देश के चयन के लिए सूक्ष्म आर्थिक संकेतकों पर विचार करने का प्रावधान है। चीन के

- लिए एक प्रतिनिधि देश के रूप में कतर पर विचार करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपने प्रस्ताव में ऐसे किसी कारक पर विचार नहीं किया गया है। कतर और चीन के विकास संकेतकों के स्तर में भारी अंतर है।
- ब. चीन के लिए कतर को एक प्रतिनिधि देश के रूप में लेना समानता और कानून के समान संरक्षण के सिद्धांतों के विरुद्ध है, पाटनरोधी नियमावली और पाटनरोधी करार के विरुद्ध है।
- भ. कतर से कीमतें उच्चतर हैं क्योंकि भारत में बाजार कीमतें चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सीमा से भी अधिक हैं।
- म. कतर बाजार में उचित वसूली निकालने के लिए कतर में विद्यमान वास्तविक कीमतें ली जानी चाहिए अथवा चीन से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की सीमा तक सीआईएफ कीमतें समायोजित की जाएं।
- य. भारत में कतर से समुद्री भाड़े को भी 40 अमेरिकी डॉलर/मी. टन से 64.47 अमेरिकी डॉलर/मी. टन में संशोधित किए जाने की भी आवश्यकता है।
- कक. प्राधिकारी के अनुरोध पर असंबद्ध आयातक द्वारा पुनः बिक्री कीमत की पूरी सूचना देने के बावजूद प्राधिकारी ने विगत परिपाटी के विरुद्ध दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव किया है।
- खख. इस सूचना को डीजीसीआईएंडएस तथा डीजी सिस्टम से जांचा जा सकता है, जैसा कि उत्पादक एवं निर्यातक द्वारा किए गए लेन-देन वार निर्यातों के लिए किया गया था।
- गग. उत्पादक की निर्यात कीमत पर विचार करना सीधे ही अनकोटेड कॉपीयर पेपर के मामले में लिए गए प्राधिकारी के दृष्टिकोण के विरुद्ध है। उस जांच में निर्यातकों के उत्तर इस आधार पर रद्द कर दिए गए थे कि असंबद्ध आयातकों ने ब्यौरे नहीं दिए। तथापि, यह सूचना वर्तमान मामले में उपलब्ध है।
- घघ. यदि प्राधिकारी उत्पादक से निर्यात कीमत पर विचार करना चाहते हैं तो फिर वैट को भी कारखानागत निर्यात कीमत में समायोजित किए जाने की आवश्यकता है।
- ङङ. आयातकों (पैरा 14) ने मौखिक सुनवाई के दौरान प्राधिकारी को बताया था, परंतु कोई लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए जो कि मौखिक सुनवाई के अनुसरण में एक अनिवार्य आवश्यकता है। किसी लिखित अनुरोध अथवा दावे के अभाव में प्राधिकारी ने उपर्युक्त पक्षकारों द्वारा दी गई उक्त सूचना पर विश्वास करने का विचार किया है जिसकी प्रतियां आवेदक को नहीं दी गई हैं अथवा सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
- चच. प्राधिकारी ने अन्य आयातकों से उनके दावों को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान करने हेतु नहीं कहा है जबकि निर्यातकों तथा आयातकों से विस्तृत सूचना मांगी गई थी। इस संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि क्या उन आयातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए अथवा पुनः बिक्री की सूचना प्रदान की अथवा प्रविष्टि के बिल अथवा कोई खाता वही प्राधिकारी को दिए।
- छछ. यह देखा जाना है कि आयातक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए घरेलू उद्योग का समर्थन क्यों कर रहे हैं। साथ ही, उपर्युक्त दो आयातकों में से एक आयातक के विरुद्ध उनके आयातों पर लगाए जाने योग्य पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से बचने के लिए चीन से आयातित संबद्ध सामानों के अधिक मूल्यांकन में शामिल होने के लिए डीआरआई जांच चल रही है।
- जज. यदि किसी उत्पादक/निर्यातक ने सामानों का पाटन नहीं किया है तो वह शून्य अथवा कम शुल्क का पात्र होगा। इसका कोई अर्थ नहीं है कि क्या पाटन मार्जिन मूल जांच के भाग के रूप में निर्धारित किया जाता है अथवा नियम 22 के अनुसार किया जाता है।
- झझ. निर्यातक ने लेन-देनों के ब्यौरे दिए हैं जिनका प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है। साथ ही, आयातकों ने पुनः बिक्री कीमत संबंधी सूचना दी है।
- ञञ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदकों की निर्यात कीमत पर प्रश्न उठाने के विरुद्ध कोई साक्ष्य दायर नहीं किया है। ऐसी सूचना के अभाव में पाटन मार्जिन उपर्युक्त सूचना के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।
- टट. निर्यात कीमतें सर्वाधिक उपयुक्त और सही हैं। ऐसे कई आयातक हैं जिन्होंने संभवतः पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी का ध्यान रखने के लिए अपने आयातों का कम मूल्यांकन किया है और इनमें से कुछ आयातकों के विरुद्ध डीआरआई जांच भी चल रही है।

आयातकों द्वारा टिप्पणियाँ

(iii) मैसर्स संदीप ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.

- पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए भारतीय आयातक, चीनी निर्यातक और चीनी उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद का बीजक अधिक बनाया है। चीनी उत्पादकों द्वारा अधिक लाभ से इसका निर्धारण किया जा सकता है।
- जबकि, भारतीय आयातक ने लाभ के तहत विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है, आयातक ने पाटनरोधी शुल्क की गारंटी की देयता पर विचार नहीं किया है। यदि पाटनरोधी शुल्क की गारंटी की देयता पर विचार किया जाता है तो विचाराधीन उत्पाद भारतीय आयातक द्वारा हानि पर बेचा जाता है।

- iii. निर्यात घोषणा प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- iv. अन्य चीनी उत्पादक/निर्यातक के आंकड़ों का पुनर्समाधान किया जाना चाहिए।
- v. अन्य भारतीय आयातक के आंकड़ों का पुनर्समाधान किया जाना चाहिए।
- vi. चीनी निर्यातक एवं चीनी उत्पादक का व्यक्तिगत सत्यापन किया जाना चाहिए।
- vii. आयातक द्वारा अनंतिम मूल्यांकित और प्रभार से बाहर प्रविष्टि बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- viii. लेखापरीक्षक ने बिक्री बीजक का सत्यापन किया, विचाराधीन उत्पाद का लाभ हानि विवरण, बिक्री आदेश/बिक्री संविदा/प्रोफार्मा बीजक/भुगतान तथा अन्य संबद्ध दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ix. एनएसआर में विचाराधीन उत्पाद के निर्यात 31 दिसंबर, 2018 के बाद क्यों रोके गए थे।
- x. आयातक ने पाटनरोधी शुल्क का भुगतान नहीं किया है, यह सरकार को हानि है। उन्होंने केवल गारंटी दी है। गारंटी को लेखांकन विवरण में उल्लिखित किया जाना चाहिए था। ऐसे संबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- xi. केवल दो आयातक ही क्यों संलिप्त हैं।
- xii. पुरानी एनएसआर में कमियों का अनुचित लाभ लेकर कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

(iv) मैसर्स सुनीता कॉमर्शियल्स प्रा. लि.

ऐसा लगता है कि प्राधिकारी इस निर्यातक को अलग पाटन मार्जिन देने का विचार कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो हमारे पूर्व अनुरोध और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध, जो पर्याप्त रूप से यह सिद्ध करते हैं कि निर्यातक के प्रमाण पत्र, निर्यात कीमत, आयातकों, आयात कीमत अत्यधिक संदेहास्पद हैं, उनको देखा जाए।

चूंकि, हम देश में मेलामाइन का नियमित रूप से आयात और बिक्री करते आ रहे हैं, अतः हम बाजार क्रियाकलापों से पूर्णतः अवगत हैं तथा विश्वास करते हैं कि यह याचिका शून्य अथवा कम शुल्क की मांग करने का प्रयास है तथा इसीलिए अलग शुल्क के लिए इस अनुरोध को रद्द किया जाए।

च. प्राधिकारी द्वारा जांच

29. सामान्य मूल्य (एन वी) की गणना

प्राधिकारी सामान्य मूल्य की गणना के सिद्धांत के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं और मानते हैं कि न्यू शिपर समीक्षा की मांग करने वाले आवेदक उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली दायर नहीं की, यहां तक कि यद्यपि, उत्पादक/निर्यातक ने नियम 22 के अनुसार उन्हें अलग पाटन मार्जिन प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया था। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में उपयुक्त सामान्य मूल्य के सिद्धांत पर विचार करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 का सहारा लिया है। आवेदक उत्पादक/निर्यातक सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उस देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य पर विचार करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का सुझाव नहीं दिया है। उत्पादक/निर्यातक यद्यपि, एम ई टी का दावा न करने का विकल्प लेते हैं तो साथ ही या तो याचिका में अथवा जब प्रश्नावली का उत्तर दायर किया जाए, पैरा-7 के पहले उपबंध को लागू करने पर विचार करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश का सुझाव नहीं लेते हैं।

अनुबंध-1 के पैरा-7 के दूसरे परंतुक में दूसरे देश से भारत सहित दूसरे देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमत का सुझाव है अथवा उपयुक्त लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर जहां यह संभव नहीं है।

इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैरा-7 में यह भी स्पष्ट है कि "बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे उपयुक्त देश का चयन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबंधित देश के विकास स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त तरीके से किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना को उचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी भी समान मामले में की गई जांच की समय सीमा के भीतर, जहां उचित हो, लेखे दिए जाएंगे। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन के अनपयुक्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और उनकी टिप्पणियां देने के लिए उपयुक्त समयावधि दी जाएगी।"

प्राधिकारी नोट करते हैं कि फरवरी, 2019 में मौखिक सुनवाई के बाद ही यह हुआ था कि आवेदक उत्पादक/निर्यातक ने भारतीय उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य के सिद्धांत को अपनाने का सुझाव दिया था और घरेलू उद्योग ने तीसरे देश अर्थात् सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए कतर से आयातों को अपनाने का सुझाव दिया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देश की

बाजार अर्थव्यवस्था के विकल्प के आधार पर अनुरोध के अलावा आवेदक उत्पादक/निर्यातक ने भी यह तर्क दिया है कि उपयुक्त समय और प्रत्युत्तर की प्रतियां उन्हें नहीं दी गई हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि "एन एस आर" के मामले में मूल जांच की तुलना में जहां जांच की अवधि पाटनरोधी नियमावली के नियम-22 के अनुसार निर्यात करने के लिए आवेदक उत्पादक/निर्यातक को सक्षम बनाने हेतु संभावित अवधि है, वहां प्राधिकारी आवेदक उत्पादक/निर्यातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोध/उत्तर, जो भी स्थिति हो, दायर करने के बाद ही सामान्य मूल्य के लिए सिद्धांत अपनाने के संबंध में अपना दृष्टिकोण दे सकते थे। प्राधिकारी ने अपना दृष्टिकोण 22.5.2019 के अपने प्रकटन विवरण में प्रकट किया और आवेदक उत्पादक/निर्यातक के अनुरोध पर 7.6.2019 तक टिप्पणियां दायर करने के लिए समय भी बढ़ाया। मामले के वास्तविक मैट्रिक्स में प्राधिकारी मानते हैं कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सिद्धांत के विकल्प का उत्तर देने हेतु आवेदक उत्पादक/निर्यातक सहित हितबद्ध पक्षकारों को उपयुक्त अवसर प्रदान किया गया है। प्राधिकारी दोहराते हैं कि प्रत्युत्तर का आदान-प्रदान प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार नहीं किया गया है और यह कि ये सभी अनुरोध प्रकटन में दिए गए थे। साथ ही प्राधिकारी ने मौखिक सुनवाई और प्रकटन के बाद किए गए सभी संगत अनुरोधों को हल कर दिया है तथा आगे कोई सुनवाई आवश्यक नहीं समझी गई है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने उल्लेख किया है कि प्राधिकारी ने प्रतिनिधि देश का चयन करने के लिए स्थापित प्रक्रिया नहीं अपनाई है जिसे जांच की शुरुआत में किया जाना चाहिए। प्राधिकारी दोहराते हैं कि यह "एन एस आर" एक वर्ष की संभावित जांच की अवधि पर जांच होने के नाते और 18 माह की पूर्णता की अवधि के साथ आवेदक उत्पादक/निर्यातक द्वारा उत्तर दायर करने के बाद ही उल्टी गिनती शुरू होती है। प्राधिकारी यह कल्पना नहीं कर पाए कि आवेदक उत्पादक/निर्यातक, जिसने एन एस आर की मांग की है, एम ई टी प्रश्नावली दायर नहीं करेंगे और न ही अनुबंध-1 के पैरा-7 के तहत निर्धारित किसी विकल्प का सुझाव देंगे। सामान्य मूल्य के परिकलन के संबंध में सुझाव सुनवाई के बाद उत्पादक/निर्यातक दोनों तथा घरेलू उद्योग के द्वारा दिए गए थे जिसकी प्राधिकारी ने अनुबंध-1 के पैरा-7 में निर्धारित अनुक्रम और इस संबंध में विभिन्न दिशा निर्देशक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए जांच की।

जहां तक विकास के स्तर के मद्देनजर सामान्य मूल्य के लिए कतर का भिन्न होने के नाते एक उपयुक्त देश न होने का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि भारत को कतर के निर्यात मात्रा की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे हैं। पैरा-7 में उल्लेख किए गए अनुसार "विकास का स्तर" की तुलना संगत है, यदि कतर में कीमतों और निर्मित मूल्य पर विचार किया जाए। भारत में कतर की निर्यात कीमतें कतर के विकास के स्तर पर आकस्मिक नहीं हैं परंतु भारत में घरेलू उद्योग की कीमतें घरेलू उद्योग और अन्य निर्यातक देशों की कीमतों के निर्धारण से स्थापित हैं। पैरा-7 के अंतिम परंतुक में भी भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत पर विचार करने की अपेक्षा है। चूंकि कतर मात्रा में संबद्ध देश का अगला गैर-पाटित स्रोत है, जो अनुचित व्यापार को ठीक करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के अध्यधीन हैं, उसका विकल्प पाटनरोधी नियमावली के पैरा-7 (अनुबंध-1) के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त है। आवेदक उत्पादक/निर्यातक ने अनुरोध किया है कि कतर से आयात की सी आई एफ कीमत चीन से आयात पर पाटनरोधी शुल्क की सीमा तक समायोजित की जाए जिसे प्राधिकारी औचित्यपूर्ण नहीं मानते हैं क्योंकि चीन से आयात कीमत नियमों के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाकर उचित एवं क्षति रहित स्तर तक ठीक की गई है। अन्य स्रोतों से निर्यात कीमत भी चीन से संशोधित उचित कीमत का निर्धारण करती है।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने उसके बाद भारत में कतर की कारखानागत निर्यात कीमत का परिकलन करते समय अपनाए जा रहे समुद्री भाड़े का भी विरोध किया जोकि सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए एक समायोजन माना जाता है। प्राधिकारी ने कतर से एक निर्यातक द्वारा एक विगत जांच में उनके पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर समुद्री भाड़े का प्रस्ताव किया था जिसका प्राधिकारी ने सत्यापन किया था। आवेदक द्वारा प्रदान किये गए साक्ष्य का घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों और दिए गए साक्ष्य के साथ सह-संबंध बनाया गया था और प्राधिकारी मानते हैं कि प्राधिकारी द्वारा माना गया समुद्री भाड़ा और प्रकटन में उल्लिखित भाड़ा उपयुक्त और उचित है।

अतः प्राधिकारी प्रकटन में उल्लिखित सामान्य मूल्य परिकलन संबंधी सिद्धांत की पुष्टि करते हैं और मानदंडों को अपनाकर अपनी सतत परिपाटी के अनुसार, जैसा कि कतर से सी आई एफ कीमत से समान/सदृश स्थितियों में सतत रूप से किया जाता है, उत्पादक/निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार समुद्री भाड़ा, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, ऋण लागत, समुद्री कीमा, बैंक प्रभार और अतिरिक्त रूप से कमीशन (एफ ओ बी का 1.5 प्रतिशत) पर समायोजन की अनुमति देने के बाद पुष्टि करते हैं। प्राधिकारी पूर्वोक्त समायोजन को शामिल करते हुए सामान्य मूल्य की पद्धति की पुष्टि करता है

30. कारखानागत निर्यात कीमत

प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक उत्पादक/निर्यातक ने अनुरोध किया है कि वैट राशि, जिसकी निर्यातक को प्रतिपूर्ति नहीं की गई है, समायोजित की जाए और तदनुसार कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित की जाए। प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान मामले में न तो निर्यातक और न ही उत्पादक की प्रश्नावली के उत्तर में इस समायोजन के लिए कोई दावा किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्यातक की संबद्ध सामानों की बिक्री लाभप्रद पाए जाने पर कारखानागत स्तर पर निर्यातक के निवल कर (वैट) में उत्पादक की बिक्री कीमत उत्पादक के लिए संगत कारखानागत निर्यात कीमत है क्योंकि पाटन मार्जिन का परिकलन उत्पादक के लिए किया जाता है। आवेदक उत्पादक/निर्यातक ने यह अनुरोध नहीं किया है कि उत्पादक के लिए कारखानागत निर्यात कीमत का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से

यह मौलिक दृष्टिकोण उपयुक्त क्यों नहीं है। जब भारत में निर्यातक की कीमत लाभप्रद ली गई है जो यह दर्शाता है कि उत्पादक से निर्यातक की कीमत विश्वसनीय है। अतः प्राधिकारी *** डॉ./मी.ट. के रूप में प्रकटन में उल्लिखितानुसार उत्पादक के लिए कारखानागत निर्यात कीमत के सिद्धांत और परिकलन की पुष्टि करते हैं।

उपर्युक्त के आधार पर उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन (30-35%) के रूप में मूल्यांकित किया गया है।

31. अन्य मुद्दे

प्राधिकारी बीजक कम अथवा अधिक बनाने के पहलु के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं और यह कि आवेदक उत्पादक/निर्यातक से क्रेताओं/आयातकों को छोड़कर आयातकों के उत्तरों को प्राप्त किया जाए तथा कीमतें सत्यापित की जाएं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी आयातक ने इस जांच में सुनिर्मित उत्तर दायर नहीं किया है। यद्यपि, उत्पादक/निर्यातक के लिए भारत में उनके दो आयातकों/क्रेताओं के लिए अधिवक्ता द्वारा कुछ आंकड़े दायर किए गए हैं तथापि, उनके द्वारा भी कोई सुगठित उत्तर दायर नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के आयात कीमत पैटर्न की जांच करने के लिए इस अवधि के दौरान डी जी सी आई एंड एस तथा डी जी सिस्टम से लेनदेनवार आंकड़े प्राप्त किए। इसका व्यापक विश्लेषण प्रकटन में भी दर्शाया गया था।

जहां तक अधिक बीजक बनाने का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि उन्होंने उत्पादक की कारखानागत निर्यात कीमत का मूल्यांकन निर्यातक को उनकी बिक्री कीमत के अनुसार मूल्यांकित की है, निर्यातक द्वारा अधिक बीजक बनाने, यदि कोई है, के संबंध में चिंताओं को ध्यान में रखा गया है।

32. निष्कर्ष :

- प्राधिकारी मानते हैं कि उत्पादक द्वारा निर्यात की मात्रा भारत में लक्षित निर्यात की कारखानागत कीमत का मूल्यांकन करने के लिए निर्यातक अर्थात् मै. फोशन कैसीनो बिल्डिंग मैटीरियल कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) को इस बिक्री के संदर्भ में पूर्णतः उपयुक्त है।
- उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का पाटन किया है।
- नियम 22 के अनुसार जैसा कि उपर्युक्त पैरा 30 में उल्लेख किया गया है, पाटन मार्जिन की मात्रा उत्पादक अर्थात् मै. क्विंटन जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (उत्पादक) को पाटनरोधी शुल्क के रूप में अवार्ड की जाती है।

33. सिफारिशें

उपर्युक्त के मद्देनजर निम्नलिखित शुल्क तालिका में उल्लिखित पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है :

उपर्युक्त के मद्देनजर नीचे उल्लिखित पक्षकारों के संबंध में निम्नलिखित शुल्क तालिका में उल्लिखित पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है :

दिनांक 8/1/2016 का सी. सं. 2/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए शुल्क के अन्य सभी पहलू अपरिवर्तित रहते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1.	2933 6100	मेलामाइन	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	मै. क्विंटन जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि.	मै. फोशन केसीनो बिल्डिंग मैटीरियल कं. लि.	319.04	मी.ट.	अम.डॉ.
2.	2933 6100	मेलामाइन	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	मै. क्विंटन जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि.	मै. फोशन केसीनो बिल्डिंग मैटीरियल कं. लि. से इतर कोई	331.10	मी.ट.	अम.डॉ.
3	2933 6100	मेलामाइन	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	मै. क्विंटन जिनजियांग	कोई	331.10	मी.ट.	अम.डॉ.

				से इतर कोई भी देश	कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि.				
--	--	--	--	-------------------------	-----------------------------	--	--	--	--

34. दिनांक 20/3/2018 की सी. न. 11/2018- सीमाशुल्क (एडीडी) के अनुसरण में मै. मै. क्वीटन जिनजियांग कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि. (उत्पादक) द्वारा उत्पादित सामानों का मै. फोशन कैसीनों बिल्डिंग मैटेरियल कं. लि. (निर्यातक) द्वारा किए गए निर्यात उपर्युक्त पैरा 33 में संस्तुत पाटनरोधी शुल्क के अनुसार विनियमित किए जाएं। यह शुल्क दिनांक 28-1-2016 की सी. सं. 2/2016- सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की अवधि के साथ समाप्त होगा।

आगे की प्रक्रिया

35. इस अंतिम जांच परिणाम के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2019

FINAL FINDING

(C. No. 04/2017)

Subject: New Shipper Review under Rule 22 of Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 pertaining to Anti-Dumping Duty imposed on the imports of Melamine originating in or exported from China PR as requested by M/s Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd (Producer) and M/s Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd (exporter) initiated on 1st January, 2018.

No. 7/11/2017- DGAD. Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

- The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") through the 2nd SSR regarding imports of "Melamine" (hereinafter referred to as "subject goods") into India originating in or exported from China PR (subject country) recommended AD duty on subject goods vide notification No. 15/17/2014-DGAD dated 5.12.2015 implemented by Customs Notification No. 02/2016-Cus (ADD) dated 28-01-2016. The original AD duties were levied on the subject goods from the subject country vide Final Findings Notification No. 14/16/2003-DGAD dated 3.9. 2004 and Customs Notification No. 107/2004 dated 16.11.2004. Thereafter the first SSR was concluded vide Final Findings Notification No. 15/29/2008-DGAD dated 20.11.2009 and implemented through Customs Notification No. 10/2010-Customs dated 19.02.2010.
- The Authority in the second sunset review recommended a fixed AD duty instead of the reference price which was imposed during the 1st SSR on noting during the investigation that the reference price was being circumvented through over invoicing by importers. None of the producers/exporters had cooperated during the 2nd SSR and, same quantum of AD duty was recommended for all producers/exporters.
- M/s. Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd (Producer) and M/s Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd (exporter) (hereinafter referred to as "New Shippers" or "Applicants") filed a duly substantiated application before the Authority in accordance with Rule 22 of the AD Rules read with the Customs Tariff Act, requesting for a New Shipper Review (NSR) in respect of the definitive anti-dumping duty imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 02/2016- Customs (ADD) dated 28.1.2016, concerning imports of the subject goods, originating in or exported from China.
- The Act and the AD Rules made thereunder require the Authority to undertake a New Shipper Review for the purpose of determining individual margin of dumping for any exporter or producer in the exporting country in

question who has not exported the subject goods to India during the period of investigation of the original anti-dumping investigation from the subject country and further that the applicant is not related to any of the exporters and producers in the exporting country who are subjected to the antidumping duty. The applicant claimed that they are not related to any of the exporters/producers in China against whom anti-dumping measures are in force with regard to the subject goods. Furthermore, they claimed that they have not exported the product concerned during the period of investigation of the original investigation.

6. The Authority after prima facie examining the request submitted by the applicant initiated a new shipper review investigation in accordance with the provisions of Rule 22 of the AD Rules vide Notification F. No. 7/11/2017-DGAD dated 1.1.2018.
7. Ministry of Finance notified the provisional assessment on all exports of the subject goods made by applicants till completion of the subject NSR investigation vide Notification No. 11/2018- Customs (ADD) dated 20.3.2018.
8. The period of investigation for the purpose of this New Shipper Review has been considered as 1st January, 2018 to 31st December, 2018.

A. PROCEDURE

9. The procedure described below has been followed with regard to the present investigation:
 - (i) The Authority issued a public notice vide Notification No. 7/11/2017 on 1st January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject NSR anti-dumping investigation.
 - (ii) The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the applicant along with a copy of the exporter's questionnaire and gave them opportunity to make their views known in writing, and filing relevant data in the prescribed Questionnaire, after expiry of the POI.
 - (iii) The Authority also forwarded a copy of the initiation notification to the Embassy of China PR in New Delhi, India.
 - (iv) The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the known domestic producers in India and gave them opportunity to make their views known in writing.
 - (v) In response to the initiation notification, Questionnaire response was filed, the applicant M/s. Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd (Producer) and M/s M/s. Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd (exporter). The producer/exporter however has not filed the questionnaire claiming market economy status.
 - (vi) Arguments raised and submitted by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this disclosure statement.
 - (vii) Non-confidential version of the evidence presented by various interested parties was made available in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
 - (viii) The Authority held Oral Hearings on 14.2.2019 to provide an opportunity to the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6). The interested parties were allowed to present rebuttal rejoinders on the views/information presented by other interested parties. The Authority has considered submissions received from interested parties appropriately.
 - (ix) Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary. The data submitted by the Applicant was examined and verified through desk study and relevant back-up documents were called for, wherever required.
 - (x) The Authority issued a disclosure statement dated 22/5/2019 as per rule 16 and invited comments from the interested parties by 3/6/2019. However on request of time extension the Authority extended the same till 7/6/2019.
 - (xi) *** in the statement represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the AD Rules.
 - (xii) Exchange Rate of Rs. 69.26 per USD has been adopted for POI.

The confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them have been examined. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties, along with non-confidential summary thereof, has been treated confidential.

- All relevant Submissions/comments made by interested parties, during the course of this investigation have been considered and included in this disclosure statement.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

10. The product under consideration in the original as well as sunset review investigation is “Melamine, a tasteless, odourless, non-toxic pure chemical powder, originating in or exported from China. Melamine is reacted with formaldehyde and made into resins or moulding powder for making innumerable products of beauty and utility”.
11. Melamine is classified under ITC HS 29336100 under the Chapter 29 of the Customs Tariff Act.

C. SUBMISSIONS BY VARIOUS INTERESTED PARTIES AND DOMESTIC INDUSTRY :

12. Submissions by the Domestic Industry:

- i. Petitioner has made contradictory and vague statements in the Petition. It is unclear whether the Petitioner has exported the subject goods to India.
- ii. A new format for NSR applications has been prescribed by the Authority vide Trade Notice 08/2018 on 25th April, 2018. The application has been filed as per the old format and no efforts have been made by the Applicant to update the application into the new format. As a consequence, the application lacks important information that is necessary to justify the need for initiation and decide the merits of the case.
- iii. The law recognizes the need for a New shipper review, and an investigation is carried out if the applicant satisfies all the three criterion for initiation of a NSR investigation, i.e. (a) they are genuine/bona-fide exporters who have made bona-fide sales; (b) they have not exported goods in the original investigation; and (c) they are not related to producer or exporter of subject goods who is attracting anti-dumping duty. However, the Applicant in the current investigation does not fulfill the criteria.
- iv. The petition does not provide any information and necessary evidences on fulfillment of conditions of eligibility under Rule 22 by Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd. (exporter). Therefore, no comments can be made on the eligibility of Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd for initiation of a NSR investigation.
- v. Investigation was initiated on 1st January, 2018 and no evidences have been placed on record yet to show the fulfillment of eligibility criteria by the Applicant. The Domestic Industry will not be able to offer comments if any evidence is producer at this late stage of the investigation.
- vi. Prospective POI, as in the current investigation, is inappropriate and contrary to law, as stated by the CESTAT in H&R Johnson (India) Limited v. Ministry of Finance.
- vii. Due to the prospective POI, the applicant has been able to manipulate and doctor the prices by (a) by doing an insignificant number of transactions (b) ceremonial volume of exports, (c) at high prices.
- viii. The sales examined for arriving at an individual dumping margin should be genuine in nature. The sales should be bona-fide commercial transactions. They should not be used as a mere tool to achieve a lower dumping margin through manipulation by a few doctored high priced transactions.
- ix. Other jurisdictions like Brazil, China, USA, Turkey, Taiwan, EU and Vietnam mandate, by law, existence of substantial/ sufficient quantity of bona-fide exports from the Applicant.
 - Brazil provisions on NSR include that in event of substantial quantities of Brazilian imports of the applicant's product within a period of six months, information on the manufacturing costs and normal value of the like product in the exporting country shall be included in the application, in addition to information on the export volume and price to Brazil as well as any adjustments required for the purpose ensuring a fair comparison. The application shall be filed up to 4 months from the termination of the period provided above.” Brazil has imposed following conditions regarding the import of melamine:
 - There must be Brazilian Imports of the applicant's product within a period of six months.
 - Such import must be in substantial quantities.
 - The application must be made within a period of 4 months from the termination of the above period.
 - China PR also provides that the applicant for new shipper must be a party who has actually exported the product under the investigation to the People's Republic of China after the original Period of Investigation. Article 5 the applicant for new shipper review must be the party who has actually exported the product under investigation to the People's Republic of China after the original period of investigation. The export mentioned in Article *shall be made in sufficient quantities so as to constitute the basis for determination of the ordinary export price. Such quantities shall be established on the*

basis of transaction volume under the normal commercial conditions of the product under investigation.” The conditions to be fulfilled by the applicant are mentioned below:

- The applicant must have actually exported the product under investigation to China after the original period of investigation.
- The exports must be made in sufficient quantities to allow determination of ordinary export price.
- Whether the exports have been made in sufficient quantities shall be established on the basis of transaction volume under the normal commercial conditions. The Chinese law further provides that the *“investigation period for new shipper review shall be 6 months prior to the submission of the application.”* The domestic industry has mentioned that the present case concerns China and that a Chinese producer cannot demand a treatment more favourable than what its own country grants to foreign producers.

- US Laws provides that an exporter must have actually exported the subject goods or sold the product for export, as a precondition for making a request for a new shipper review. *“Subject to the requirements of section 751(a)(2)(B) of the Act and this section, an exporter or producer may request a new shipper review if it has exported, or sold for export, subject merchandise to the United States.”* The first two questions of the checklist for filing an application for new shipper review are also on the issue:

“a. Has exported, or has sold for export, subject merchandise to the United States? (Section 351.214(b)(1))”

“b. Has made an entry for consumption in the United States, or sold the subject merchandise to an unaffiliated customer during the relevant period of review (there must be either a sale or entry during the new shipper POR to proceed with initiation)? (Section 351.214(f)(2)(i)).”

US carries out a bonafide sales test, as is evident from the extracts of Issues and Decision Memorandum for Final Rescission of “Issues and Decision Memorandum for the Final Rescission of the Antidumping Duty New Shipper Review of Honey from the People’s Republic of China: Shanghai Sunbeauty Trading Co. Ltd.” [A-570-863]: The US Court of International Trade has upheld the use of the bona fide sales test. The rationale behind the test stems simply from the fact that an exporter should not be allowed to get the benefit of a lower margin on the basis of a few atypical transactions. A new shipper review should not be allowed to be used as a tool for the exporters to gain an undue advantage by stage managing their business.

- Article 11(4) of the Regulation (EU) 2016/1036 of The European Parliament and of The Council of 8 June 2016 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union provides as under with reference to New Exporter Reviews: *“The review shall be initiated where a new exporter or producer can show that it is not related to any of the exporters or producers in the exporting country which are subject to the anti-dumping measures on the product, and that it has actually exported to the Union following the investigation period, or where it can demonstrate that it has entered into an irrevocable contractual obligation to export a significant quantity to the Union.”* The European Union also requires that a review be initiated only where the exporter has either exported the subject goods or has entered into an irrevocable contractual obligation to export a significant quantity to the European Union.

- Turkey has similar provisions to that of the European Union and with regard to eligible applicants of a New Exporter Review as under;

“Article 8- The decision for definitive measures may be reviewed upon request by the new producer or exporters which have not exported the product concerned during the period of investigation and which can show that they are not related to any of the exporters or producers whose products are currently subject to the definitive measures. However, producers or exporters requesting such a review should have either actually exported the product concerned to Turkey following the investigation period or entered into an irrevocable contractual obligation to export a significant quantity of it. A new exporter review shall be carried out on an accelerated basis to determine the margin of dumping or amount of subsidy for those who made the request.”

- The Regulations Governing the Implementation of the Imposition of Countervailing and Anti-Dumping Duties of Taiwan also provide that an exporter may apply for a new shipper review only if such an exporter has exported significant quantity of the product concerned. Further, the application may be made only after one year following the commencement of exports.

“Article 35-1 Foreign producers or exporters of the case may apply for the new shipper review to MOF with relevant documents or proof of evidence, and request for an individual dumping margin, respectively, provided that:

- no exportation of product concerned to Taiwan during the period of investigation.
- they can show that they are not related to any of the exporters or producers of the case, and they have not exported the product concerned to Taiwan during the period of investigation.
- they have exported a significant quantity of the product concerned to Taiwan following the original period of investigation.

- Under Vietnam Law requires that an applicant filing for a new shipper review satisfy the following three conditions:

- The applicant has no relationship to producers/exporters subject to duty
- The applicant has actually exported to Vietnam after the period of investigation of the original investigation,
- The volume of exports to Vietnam is large enough for the investigating authority to determine a reasonable export price. The volume of exports would be seen at the time of filing of the application.

The global practice on the issue of new shipper review is very clear in that the following requirements must be satisfied by an applicant making a request for a new shipper review:

- The applicant must not have exported the subject goods to the investigating country during the period of investigation of the original investigation;
- The applicant must not be related to any producer or exporter who has been subject to anti-dumping on the product under consideration;
- The applicant must have exported the subject goods to the investigating country after the period of investigation of the original investigation;
- The exports must have been made in sufficient or significant quantities so that the export price is representative; and
- Such exports must be made before the application has been filed.

x. The domestic industry has mentioned the following regarding the Indian practice and jurisprudence in NSR applications with regard to “commercial/significant quantity of exports”,

- The Indian law does not require that the exporter must have made exports before an application for new shipper review may be made; however, the recent practice of the Designated Authority and the decisions of the Court lead to the same conclusion. It may be noted that initially the Designated Authority had considered prospective period of investigation. However, such a practice was also frowned upon by the Tribunal in the case of H and R Johnson (India) Limited Vs. Designated Authority, reported in 2007 (212) E.L.T. 130 (Tri. - Del.) in judgment dated 15th February, 2007.

xi. Again, in decision dated 27th August, 2007, in the case of H and R Johnson (India) Limited Vs. Ministry of Finance in Appeal Number 1/2007 – Anti-Dumping, the Tribunal clearly held that the use of prospective period of investigation was not tenable in case of a new shipper review. Further the Tribunal laid down that the following conditions must be satisfied for an exporter to make an application for a new shipper review:

- The applicant for new shipper review must be the party who has actually exported the product under investigation to India after the original period of investigation.
- Such exports should have been made in sufficient quantities so as to constitute the basis for determination of the export price.
- Such quantities shall be established on the basis of transaction value under commercial conditions of the product under investigation.
- For a meaningful investigation, the investigation period for determining the dumping margin for the new shipper, should ordinarily range between six months to twelve months prior to the submission of the application.

The above principles have also found a place in the recent findings, the Designated Authority has taken cognizance of the fact the exports by the new shipper must be in significant volumes so as to allow determination of a representative price. In this respect, the findings of the Designated Authority in the matter of New Shipper Review investigation concerning imports of Jute products from Bangladesh in respect of M/s. Janata Jute Mills (Producer) dated 22nd November, 2018.

xii. Similarly in “New Shipper Review investigation concerning imports of 1 1 1 2 Tetrafluoroethane or R 134a originating in or exported from China PR in respect of M/s. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd. (Producer/Exporter), M/s Zhejiang Sanmei Chemical Products Co., Ltd (Exporter) and M/s Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd (Producer)” [No.15/22/2016-DGAD] dated 26th July, 2018 the Designated Authority’s records decision be noted. The above case involved a prospective period of investigation, the above case clearly brings out that it may allow an exporter to take advantage of a lower anti-dumping duty.

xiii. In the “New Shipper Review in respect of the Anti-Dumping Duty imposed on the imports of PVC Flex Film, originating in or exported from China PR, as requested by M/s Haining Tianfu Warp Knitting Co Ltd, China PR (Producer) and M/s Manna, Korea RP (Exporter)” [No. 15/23/2011- DGAD], the Designated Authority found that in case of a small volume of exports, there was a risk that the transactions had been stage managed to obtain a lower margin. Therefore, the Designated Authority refused to allow a separate margin to the exporter, and they were relegated to the residual duty. From the above analysis and discussions, it is evident that conditions listed under Rule 22 do not suffice for an application for new shipper review. In order to ensure that an exporter does not take undue advantage of the process, the conditions as listed by the Tribunal must also be necessarily satisfied.

xiv. Trade Notice 01/2019 dated 29th January 2019 has also clarified the practice regarding existence of commercial quantity of exports to receive an individual dumping margin during a NSR investigation which inter alia states that the NSR application shall be entertained by the Authority only if the NSR applicant has undertaken actual exports to India in “commercial quantities” for the product concerned before making the application.

xv. The Authority has specifically prescribed that the quantities exported by the exporter should be in commercial quantity so as to receive an individual margin of dumping. Even though the trade notice is prospective in nature, the principle highlighted is not a new principle. The principle of actual exports been made in commercial quantity has been recognized by the Authority as well as Hon’ble CESTAT in past

xvi. The need for commercial/significant quantity of exports, along with other requirements above Rule 22, have been signified in multiple decisions by the courts and Final Findings by the Authority.

xvii Appropriateness of the import price cannot be ascertained since there are no questionnaire responses from importers. In this regard, the peculiar facts and circumstances of the case make the export price unreliable.

xviii. Excessive confidentiality has been claimed in the questionnaire responses. The non-confidential version of the questionnaire does not correspond to the Trade Notice on confidentiality, the law and practice of the Authority.

xix. Due to excessive confidentiality and insufficient information, it cannot be ascertained whether Market economy status has been claimed by the Applicant. Moreover, any such claims for Market economy treatment should be rejected on the grounds that the normal value calculation during the sunset review was carried out on non-market economy basis.

xx. If the Applicant considers that the determination should be on the basis of domestic selling price, the same shall be contrary to the practice of the Authority.

xxi. No explanation for inclusion of exporter in the channel of trade has been made by the applicant. The same can be used for manipulation by the Applicant and such unverified claims should be rejected.

xxii. Prospective POI is not justified in the present investigations since no proper reasoning has been provided by the Applicant for absence of exports during the original POI.

xxiii. There were no responding exporters in the sunset review and hence all the Chinese exporters have continued to export at the residual duty rates. When there is equal competition between all Chinese exporters, lack of individual dumping margin cannot be a proper reason for absence of exports.

xxiv A comparison of exports as per China custom data and imports as per DGCI&S data and exporters’ data shows that the responding exporter has sold the PUC at an artificially higher price as compared to other Chinese exporters.

xv. Absolutely no arguments have been made on (a) any issues pertaining to the present investigation, (b) how conditions under Rule 22 are fulfilled, (c) any submissions on pertinent submissions made by the domestic industry.

xvi. No arguments made by the Domestic Industry during the oral hearings have been responded to. (a) No evidence provided "to show" that the conditions laid down in Rule 22 have been met; (b) Requisite information to demonstrate that the exporters normal value can be considered have not been provided; (c) Bonafide sales must be shown by the exporter.

xvii. Applicant has consciously not filed any submissions in the written submissions and provides all its major claims either in the confidential version of the submissions or in the rejoinder submissions, knowing that the Designated Authority does not follow a practice of making rejoinder accessible to other interested parties. Any submissions made orally are taken into account only if it is submitted in the written submissions.

xviii. Domestic industry has determined dumping margin considering price from market economy third country to India. It would be seen that the dumping margin is in fact higher than the dumping margins determined in the POI of the original investigations.

13. Submissions by the Applicant Exporter/Producer:

- i. The Applicant did not export the PUC to India during the period of investigation of the sunset review investigation having POI as April 2014 to June 2015.
- ii. The Domestic Industry has contended that it is unclear from the petition whether the applicant has exported the product to India or not. In this regard, we submit that we have already submitted the complete information with our application to the Authority. It is clear from the application itself that the applicant has exported substantial quantity of the subject goods to India. Further, the said statement of the Domestic Industry is contradictory to their own submission of their written submissions wherein they themselves have provided the export prices of the applicant as per China customs and DGCIS data.
- iii. The Domestic Industry has made submission regarding the object, scope and purpose of the New Shipper Review. They have concluded that “while a bonafide new shipper has the right to seek individual margins, but at the same time the Designated Authority needs to ascertain that the claims are bonafide and there is no abuse/misuse/ circumvention of anti-dumping duties. It is for this reason that the applicant needs to be strictly put to establish that (a) they are genuine/bonafide exporters who have made bonafide sales (b) they have not exported goods in the original investigation and (c) they are not related to producer or exporter of subject goods who is attracting anti-dumping.”
- iv. The Applicant also certified that it is not related to any entity in any country on which anti-dumping duty on the subject goods is applicable. Thus, the Applicant satisfied both the requirements of Rule 22 of the AD Rules and was eligible for the initiation of the New Shipper Review and the determination of an individual rate of duty.
- v. The Applicant did not claim excessive confidentiality. All the documents upon which confidentiality was claimed contain business confidential information and are not available in the public domain and did not impact or prejudice the Domestic Producers.
- vi. That the concerned trade notice (Trade Notice No. 08/2018) was issued on 25.04.2018, while the present application was filed by the applicant prior to that date. In this regard, the trade notice specifically mentions that it is applicable on the applications filed ‘after’ the issuance of said trade notice. Therefore, there is no merit in the issue raised by the Domestic Industry.
- vii. In this context, it is submitted that the respondent meets all the requirements mentioned by the Domestic Industry. The initiation of the present investigation itself was done after the respondent sufficiently established that (a) they are genuine/bonafide exporters who have made bonafide sales (b) they have not exported goods in the original investigation and (c) they are not related to producer or exporter of subject goods who is attracting anti-dumping. The Authority has fully scrutinized the application and issued letter seeking additional information to satisfy themselves in accordance to the requirement of Rule 22. Therefore, the contentions of the Domestic Industry in this context, needs to be rejected. The respondent humbly requests the Authority to kindly determine the individual dumping margin for the respondents, as they have provided all the requested information for the purpose of determining an individual dumping margin for the respondents. The respondent also invites the Authority to kindly carry out the on the spot verification of the data filed by them to satisfy itself about the bonafide intentions of the respondent and the data filed by it.
- viii. That the excerpt from case cited by the domestic industry refers to an observation of the Hon’ble CESTAT which was struck down by the Hon’ble High Court of Delhi in H and R Johnson (India) Limited v. Union of India & Ors. [2008 (232) E.L.T. 390]. The High Court expressed its disapproval from observation of the CESTAT in the paragraph cited by the domestic industry and noted that in the case of a first-time shipper, a retrospective period cannot be taken. Based on this, the High Court agreed that, with respect to New Shipper Review, a prospective period of investigation must be allowed and cannot be ruled out. In view thereof, the contention of the Domestic Industry in this regard holds no merit in terms of their reasonability or legality, and therefore, should be rejected.

- ix. The pre-condition that exports should be in commercial quantum is contrary to the requirement under Rule 22 of the Anti-dumping Rules and Article 9.5 of the Anti-dumping Agreement. Rule 22 of the Anti-dumping Rules states that the Authority shall carry out new shipper review to determine individual margin of dumping if (i) the producer or exporter has not exported the product to India during the period of investigation and (ii) this producer or exporter is not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product.
- x. That the requirement of “commercial quantities” as proposed by the Domestic Industry shall encourage the concerned exporters to artificially lower down their prices to absorb the anti-dumping duties. In fact, it would be untenable for the respondent to export the subject goods at unfavourable prices in order to maximize quantity of exports even when they are competing against the prices offered by the Domestic Industry and other Chinese producers on whose goods there is no or lesser anti-dumping duties applicable. The respondent did not deviate from its standard practice and exported to India during the POI only when it was able to obtain suitable price in accordance with market demand. Further, to compare total exports from China to exports made by one producer would be unreasonable and contrary to law.
- xi. There is no requirement under Rule 22 that exports by the new shipper should be of certain minimum quantity to allow determination of individual dumping margin. Such a requirement shall add an additional obligation of “exports in commercial quantities” on the concerned exporter which is otherwise not mentioned under Rule 22. In other words, by requiring “representativeness” of exports, the Authority has imposed a condition which is not provided in Rule 22.
- xii. In the recently concluded New Shipper Review investigation concerning imports of Jute Products (F. No. 7/10/2017-DGAD, dated, 22.11.2018), the Authority granted the individual dumping margin to the applicant exporter M/s Janata Jute mills Ltd despite the fact that the concerned exporter exported merely 23MT of the subject goods in the total demand of 50,000 MT.
- xiii. The requirement of “commercial quantities” as proposed by the Domestic Industry shall encourage the concerned exporters to artificially lower down their prices to absorb the anti-dumping duties. In fact, it would be untenable for the respondent to export the subject goods at unfavourable prices in order to maximize quantity of exports even when they are competing against the prices offered by the Domestic Industry and other Chinese producers on whose goods there is no or lesser anti-dumping duties applicable.
- xiv. The Domestic industry claims that the lack of response from importers is evidence that the Respondent has somehow attempted to suppress the fact that a token export was made at unrealistic price in order to obtain a low or no dumping margin and thereafter aggressively dump the volumes. In this regard, it is submitted that the domestic industry has presented its theories and assumptions and has made no legal or factual submissions in this regard. It is submitted that the neither the respondent nor the Authority itself can compel an independent importer to participate in an ongoing investigation. Therefore, the lack of such participation does not evidence anything. The domestic industry’s submissions are merely accusatory statements and conjectures with no legal or factual merit. Therefore, we request the Authority to reject such submissions.
- xv. The Domestic Industry has stated that the applicant does not clear that on what basis they have claimed the normal value. In this regard, the respondent submits that it is a considered practice of the Authority to not accept the normal value of the Chinese producers. This fact is also well reflected in the written submissions of the Domestic Industry. Therefore, the respondent submits that the Authority may determine the normal value for the respondent on the basis of the cost of production of the subject goods produced in India.
- xvi. The Domestic Industry has claimed that a prospective POI is not justified in the present case and they cannot appreciate why the applicant did not export the subject goods to India. In this regard, the applicant submits that the claim of the Domestic Industry in the paragraphs under reply is misleading and fallacious. The respondent has made an export of 876.5 MT of the subject goods to India. Further, the said statements are also contradictory to their own submissions wherein they themselves have provided the export prices of the applicant as per China customs and DGCI&S data. The respondent is not able to appreciate that when as per the Domestic Industry there are no exports by the respondent, how there can be export prices of the applicant for their exports to India as per China customs and DGCI&S data. Clearly, the Domestic Industry is trying to confuse the Authority and therefore, their submission should be rejected in totum.
- xvii. The Domestic Industry has submitted that the export prices of the applicant for their exports to India as per China customs and DGCI&S data. While the respondent has been constrained from providing

any comments on the same due to the confidentiality claimed by the Domestic Industry, the respondent submits that the said data appears to be totally fallacious and manufactured. It is a matter of record that the DGCI&S data does not make segregation on the basis of the exports made by any particular exporter. However, the Domestic Industry has claimed to provide the export price of the respondent as per DGCI&S data in the para under reply. Clearly, the data submitted by the Domestic Industry is not actually DGCI&S data and the Domestic Industry is trying to mislead the Authority by presenting some manufactured data as DGCI&S data. In view thereof, the said submission of the Domestic Industry along with the data presented by it should be outrightly rejected.

- xviii. That in the present case, the initiation of the present investigation was done after the respondent sufficiently established that (a) they are genuine/bonafide exporters who have made bonafide sales (b) they have not exported goods in the original investigation and (c) they are not related to producer or exporter of subject goods who is attracting anti-dumping. It is further submitted that after filing of information, the Authority has fully scrutinized the application and issued letter seeking additional information to satisfy themselves in accordance to the requirement of Rule 22. Therefore, the contention of the Domestic Industry that Authority has not done due diligence is incorrect, while initiating the investigation.
- xix. That the lack of participation of unrelated importer cannot be held against the exporter. Moreover, non-participation of independent importer to participate in an ongoing investigation cannot be held against the participating exporters. The domestic industry's submissions in this context, are merely accusatory statements and conjectures with no legal or factual merit. Therefore, applicant request the Authority to reject such submissions of the Domestic Industry.
- xx. That the decision to export the goods and the channel of such exports is purely a business decision solely resting with the producer / exporter and is based upon various factors including payment policies of the importers. Moreover, this is very common practice in many countries to export through traders.

14. Submissions by Importers

Comments filled by M/s Sandeep Organics Pvt. Ltd.

- i. The new shipper review may be misused.
- ii. What is the need of a different exporter when the producer can export directly?
- iii. The exporter & producer should have same Anti-Dumping as other exporters & producers of China.
- iv. The Exporter is exporting other products also.
- v. The producer has the capacity to dump the material.
- vi. This NSR would drop local prices and can affect the profits of the domestic industry, which is suffering losses.
- vii. The central Government shall ask for provisional Anti-Dumping & the importer should apply for refund after the final findings of the review.
- viii. The Anti-Dumping amount is very big and therefore heavy Anti-dumping should be levied.

Comments filled by M/s Sunita Commercial Pvt. Ltd.

- i. We have been in this business for past more than two decades The price difference in melamine supplied by different Chinese suppliers is hardly in the region of 5-10 US\$/MT. There are more than 40 plants in China producing Melamine China currently exports Melamine in the region 3-4 lac MT per annum to various countries.
- ii. The enclosed statement of imports of melamine into India shows that the price at which the applicant company has exported the product and the price at which other Chinese suppliers have supplied the product. It would be seen that there is a difference of more than 100-200 US\$/MT in the prices at which the applicant company has exported the product to India and the price at which other Chinese suppliers have supplied the product in Indian market.
- iii. Since we are operating at retail level and interacting extensively with the consumers, we are quite aware of the price at which imported product has been resold in the market. There is no material

difference in the prices of the applicant company and the price charged by other Chinese suppliers in the market. This is not surprising considering that there is typically no significant difference in Chinese Melamine resold in the Indian market. This further shows that the export price reported by the applicant company is fictitious. Mere holding of documents does not in itself establish credibility of the price and therefore merely because the applicant can show a commercial invoice or payment proof, the same does not mean that the product was in fact sold at these prices. In limited sales transactions, these documents can easily be prepared in desired direction.

- iv. The present application is not bonafide and there is an attempt to seek no or lower ADD so that the market currently held by other Chinese producers could be easily garnered by this entity. Even though the applicant company is a very old established company, it seems that they started producing Melamine only recently. Given that there are significant surplus capacities in China and Chinese producers find it difficult to get the market, the applicant is obviously trying to create a market for itself by trying to create an unfair advantage in Indian market vis-à-vis other Chinese suppliers.
- v. If this company is given a discriminatory and lower ADD as compared to other Chinese suppliers, this company would easily garner the market that is being catered by other Chinese suppliers. India is significantly short in Melamine and therefore there is a need for import. Import price from non-Chinese sources are much higher than Chinese sources. Such being the case, even after ADD, there are significant import of Chinese Melamine in the country. On an average, 35000MT/annum Melamine is regularly being imported from China. The applicants intend to therefore garner this market readily by creating an unfair advantage.
- vi. Since we have been regularly importing and selling Melamine in the country, we are willing to provide you any further information that we may require in establishing that the price of the company is artificial.

According Individual dumping margin to the applicant

D. EXAMINATION BY AUTHORITY

15. Rule 22 of the Anti-Dumping Rules provides as follows –

“22. Margin of dumping, for exporters not originally investigated.

(1) If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product.

(2) The Central Government shall not levy anti-dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of the initiation of the review.”

16. Article 9.5 of the WTO Agreement states as under –

“9.5 If a product is subject to anti-dumping duties in an importing Member, the authorities shall promptly carry out a review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to the importing Member during the period of investigation, provided that these exporters or producers can show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. Such a review shall be initiated and carried out on an accelerated basis, compared to normal duty assessment and review proceedings in the importing Member. No anti-dumping duties shall be levied on imports from such exporters or producers while the review is being carried out. The authorities may, however, withhold appraisement and/or request guarantees to ensure that, should such a review result in a determination of dumping in respect of such producers or exporters, anti-dumping duties can be levied retroactively to the date of the initiation of the review.”

17. In terms of the aforesaid Rule, provisions in the WTO Agreement and the past practice of DGTR, a New Shipper Review investigation is to be carried out under following circumstances for the purpose of determining individual dumping margin in respect of any exporter or producer from the subject country attracting ADD:

- i. that the exporter or producer has not exported the product under consideration during the period of investigation, and
 - ii. that exporter or producer shows that they are not related to any of the exporter or producer in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product concerned.
18. In the instant case M/s.Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd (Producer) and M/s. Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd (exporter), China PR, filed an application before the Authority seeking individual dumping margin on **the imports of Melamine originating in or exported from China PR** for initiating a new shipper review. As regards the eligibility of the aforesaid producers/exporters claiming 'NSR', the Authority notes that none of the producer/exporter had participated in the second SSR investigation. The Authority in the 2nd SSR has also referenced DG-Systems data to correlate the volume and price of imports of subject goods under duty free and outside duty free category. The Authority has correlated the claim of the applicant producer/exporter of not having exported the subject goods during the original POI from the DG-Systems data considered in the earlier investigation. No interested party has provided evidence of non-fulfilment of condition by the applicant producer/exporter for NSR either on, it having made exports earlier nor on its relationship with other producer/exporter by way of any substantive evidence. The Authority therefore proposes to hold that the producer/exporter is eligible to seek a New Shipper Review in the instant case.

19. **Normal value**

- a. The Authority notes that the applicant Producer/Exporter i.e. M/s.Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd (Producer) and M/s. Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd (exporter), China PR has filed exporter Questionnaire response but have not filed the supplementary questionnaire to claim Market Economy status. In the rejoinder submissions, the applicant have claimed that it is a considered practice of the Authority not to accept the normal value of the Chinese producers and have requested that the normal value for the producer/exporter be determined by the Authority on the basis of the cost of production of the subject goods produced in India. The applicant has however not suggested any options pertaining to the first or second proviso of para 7 of the AD rules.
- b. The domestic industry in its rejoinder submissions have submitted that market economy third country export price to India be considered.
- c. The Authority notes that Normal Value for a country considered as a non market economy is required to be computed in accordance with para 7 and 8 of Annexure 1 of AD rules. In the instant case the applicant has not filed any MET questionnaire and therefore the Authority notes that options under para 7 of Annexure 1 to AD rules need to be explored. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7.
- d. The Authority also notes the existing jurisprudence on constructing the normal value in case of a non market economy contained in the Supreme Court judgement in M/s Shenyang Mastsushita S. Battery Co. Ltd. vs M/s Exide Industries Ltd. (Civil Appeal No. 6371/2003 dated 23/2/2005), Guwahati High court in M/s Century Plyboards (I) Ltd & Anr.-vs- Union of India & Anr. (W.P No. 6568/2017 dated 4/10/2018) and CESTAT, Principal Bench, New Delhi in M/s Apollo Tyres Ltd. vs Union of India (Appeal No. C/768, 600, 601, 773, 769/2005-AD-dated 9/9/2005). These judgements provide directions regarding implementation of para 7 of annexure 1 to AD rules with respect to choice of an appropriate option, and associated obligations thereof.
- e. There is no information provided by any Interested Party to consider application of the first proviso of para 7 nor any material is available with the Authority for the same. However as regards the next proviso in para 7, the Authority notes that information on import volume and prices of subject goods from countries other than China during POI is available from the DGCIS data. It is noted that while China accounts for 30303 MT, 44% of total imports of subject goods during POI, the next highest quantity of imports are from Qatar of 16479 MT constituting a share of 24.20% at a average CIF of 1450.48 \$/MT. The imports from Germany, UAE, and Japan are 12% (CIF 1530 \$/MT); 7% (CIF 1532 \$/MT) and 3% (CIF 1524 \$/MT) respectively.
- f. Qatar being a non subject country with no investigation of AD underway or AD measure in force and with import volume from Qatar being quite significant, the CIF price is thus representative of price payable in India. Also since import price of China is corrected by the existing ADD, the import price from Qatar is not impacted by any dumped price from China. The Authority notes that this option of

para 7 to construct the normal value of subject goods is appropriate and is representative of normal value of the subject goods. To evaluate the normal value, the Authority would make appropriate adjustments on various elements like ocean freight, port expenses, inland freight, credit cost, marine insurance and bank charges as per its consistent practice adopting norms as is done consistently in similar/analogous situations for arriving at an ex-factory price. The same is proposed to be compared with exfactory export price of the producer i.e. M/s Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. at the same level of trade in accordance with the rule 6(i) of Annexure 1 of AD rules. The Authority proposes to consider adjustments on to an extent of ; Ocean freight (40 \$/MT), Ocean insurance (0.5% of CIF), Inland freight (1% of FoB), Port handling (1% of FoB), Credit cost/Bank charges (1% of FoB). The next in the hierarchy of the options as per para 7 is price actually paid or payable in India for the like product duty adjusted if necessary to include a reasonable profit margin, which the Authority notes needs to be considered only if the option stated above was not available.

- g. The Authority notes that as per para 7 of Annexure 1 of AD rules, reasonable opportunity is to be provided to the interested parties on selection of the third market economy country. The Authority notes that in the ongoing NSR investigation, the time limit to complete the case has been fixed as 30/6/2019 in view of the Hon'ble High Courts order in Writ Appeal No. 412 to 414 of 2018. The exporter was provided a prospective POI of 1 year till 31/12/2018. The questionnaire response was filed by the producer/exporter on 8/2/2019. In the rejoinder submissions dated 28/2/2019, the producer/exporter stated that Authority may determine normal value on the basis of the cost of production of the subject goods produced in India methodology for constructing normal value for China while the domestic industry claimed market economy third country export price to India. The Authority undertook desk study of the applicant's questionnaire response to verify the data filed by the exporter and the producer. The Authority holds that in case of a NSR investigation which provides a prospective POI of 1 year, the time to respond to the option of market economy third country selection is quite reasonable with the case completion date being 30/6/2019 as stated above. The post disclosure comments by the exporter, domestic industry and the two importers have been dealt in the subsequent paras under the post disclosure comments and examination.

ASL representing the producer, exporter i.e M/s.Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. (Producer) and M/s. Foshan Kaisino Building Material Co. Ltd. (exporter).

Export Price –

20. The applicant producer (M/s Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd.) during the POI has sold on an ex-factory basis *** MT at a price of *** \$/MT of subject goods through 12 transactions to M/s Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd., the exporter. M/s Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd has thereafter exported the same quantity to M/s Exim Incorporation and M/s Sanjay Chemicals in India to an extent of *** MT and *** MT respectively. The producer's ex-factory selling price to M/s Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd., the exporter to India excluding VAT is claimed as *** \$/MT.
21. In support of the above exfactory price, the producer has provided its sale invoices to the exporter and the associated bank certificates. The producer in appendix 3C of the questionnaire filed by them has mentioned the sales price to M/s Foshan Kaisino Building Material Co. Ltd., and have also stated the inland freight. The producer during the desk verification clarified that the invoice raised by them on M/s Foshan is on exfactory basis and provided its sales contract with the exporter indicating delivery term on warehouse self lifting basis. The Authority therefore proposes to reference the exfactory sales price of producer to the exporter net of VAT only with no adjustment on the inland freight at *** \$/MT.
22. The exporter has sold these subject goods to the two importers as mentioned above on an ex-factory basis at a price of (*** \$/MT). In support of the aforesaid data, the exporter has provided invoices of exporter to the importers, payment received by the exporter, ledger of the two importers showing buying and resale price of subject goods. However no bill of entries have been submitted by M/s ASL, who filed some data related to importers vide letter dated 29/4/2019 in continuation of the desk study undertaken for the applicant's questionnaire. The exporter has claimed an adjustment on bank charges. Further the exporter in appendix 9 of its questionnaire response has claimed that sales of these subject goods to the customers in India are at a profit. The Authority notes that the exporter has though claimed an overall loss in the calendar years 2016 and 2017, it has claimed profitability on an overall basis in POI and also for the PUC in POI. The non PUC has been claimed to be sold on loss during POI.

The exporter in its questionnaire response in the Appendix 1 has claimed exports of some quantity of subject goods in 2017 also, to India. However the exporter has not sold the subject goods during POI and previous three years to any country other than India.

On examining the exports of subject goods to India in 2017 and in POI on parameters of cost of sales, sales value and profitability it is noted that the cost of sales claimed by the exporter declined by 3% in POI as compared to 2017 while selling price increased by 13% and profit per unit by almost 200%. In view of the profitability of the exporter on PUC sales to India during POI, the exfactory price of producer to exporter as stated above is considered appropriate and has been adopted as the exfactory export price. The post disclosure comments of the exporter have been dealt in the subsequent under the post disclosure comment and examination paras.

Representativeness of the export price and quantity of the applicant producer/exporter

23. The Authority notes that both domestic industry and importers have raised issues on representativeness and appropriateness of the export quantity and price of subject goods by the applicant new shipper to India. The Authority also notes the submissions by the applicant new shipper rebutting the above claims and underscoring the provisions of relevant AD rules and the exports made by them at the prevailing price.
24. The Authority notes that total imports of subject goods from China during POI, as per DGCIS and DG-System data corroborate and are 30303 MT and 30278 MT respectively. The exports by the applicant new shipper of *** MT constitute 2 to 3% of total imports from China during POI. The Authority notes that the CIF price of subject goods of the applicant producer/exporter during POI is quite higher as compared to the average price of subject goods from China. Though there are only a few import transactions at a price higher than the applicant producer/exporter, these are of quantities smaller than the applicant producer/exporter and also that a few of these transactions are under the duty free scheme.
25. The Authority notes that in the second SSR, the issue of over invoicing being resorted to by importers was addressed in the finding appropriately by correlating the import price with the data provided by DRI, imports prices under duty free category, and the China Customs export prices made available to the Authority during the investigation.
26. The Authority notes that domestic industry in its submissions regarding the appropriateness of quantum of exports by a New Shipper and its reasonableness have cited provisions in the Act of other countries. The Authority notes that the applicant has also stated that India's AD rules do not stipulate any threshold of commercial quantities. Further to establish the bonafide of their export price they though had submitted that an independent importer's participation can not be forced, later provided the ledger data of purchase and resale of subject goods by importers to establish that the resale price is with a markup. However bill of entries of the import transactions and the stipulated questionnaire response have not been provided. The Authority however notes that claim of the applicant on sales by the importer being with a markup needs to be seen in context of the pending determination of individual dumping margin for the new shipper, which carries a liability of paying the AD duty by the importer post completion of the new shipper review. The Authority notes that to accord an individual dumping margin to a new shipper, the Authority needs to evaluate both normal value and ex-export price. The Authority notes that the applicant new shipper has cited NSR undertaken in case of Janata Jute Mill underscoring according of an individual dumping margin to the new shipper. The Authority notes that in the same determination the Authority had emphasised the need to establish reasonableness and credibility of export price and constrained by the facts of the case had decided to only accord non-sampled category of AD duty to the applicant.
27. The submissions on this aspect made in response to the disclosure are dealt in subsequent paras.

E. POST-DISCLOSURE COMMENTS BY INTERESTED PARTIES

In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the Authority disclosed the essential facts of the present investigation to all interested parties vide disclosure statement issued on 22nd May, 2019, and advised them to file comments thereon by 3rd June, 2019. The date was later extended to 7th June, 2019 at the request of the applicants, who sought additional time to file comments on the choice of surrogate country in addition to other aspects of the disclosure statement. The comments received from the applicant and the domestic industry have been addressed in the present findings to the extent considered relevant.

28. (i) Submissions made by the domestic industry

- a. Non-confidential version of information filed by the importer is not available to the DI. It was only through the Disclosure Statement that the Domestic Industry came to know about information filed through a letter dated 29/04/2019.
- b. By the reason of prospective period of investigation, the applicant has been able to manipulate and doctor the petition by exporting to India at higher prices.
- c. The import data as per secondary sources shows that the two importers importing the material from the applicants have imported at relatively higher prices than others.

- d. All importers, ones who have comparable volumes with the applicant, and with lesser volumes too, have imported the product at a much lower prices.
- e. Only importers that have higher price are –(a) Aron Universal (specialized product used in pigments); (b) Noble Laminates Private Limited; (c) Sumilon Industries Limited; (d) Hi-Tech Agro Mills (All have imported about 22 MT or 0.1% of total import from China each; believed to be under Advance license).
- f. The China Customs data shows that the applicant has exported the product to India at relatively higher prices as compared to others.
- g. This is also evident from the response filed by the exporter (as stated in the disclosure statement) wherein they have increased profits by 200% in shipments made during period of investigation. It is inconceivable that when the cost has declined by 3%, the exporter was able to increase its selling price by 13%, thereby earning 200% higher profit than past.
- h. The case is blatantly stage managed, as can be seen from the evidence on record.
- i. The producer concerned is not a new producer in China. It was established in 12th September, 2008 and the trader concerned works in sales of tiles and has been picked up for a product having significant domestic and international business without any experience to carter a new market.
- j. The importers concerned are also fly-by-night importers, having no past experience of either trading or dealing in Melamine.
- k. The importer did not file a questionnaire response at the stage of initiation and do not have interest in the investigation. It seems, post hearing, some internal sensitive documents was selectively passed on to the legal consultants of the Chinese exporter and filed on behalf of importer.
- l. A set of new producer and exporter having no experience of selling Melamine in India are fetching a price much higher than the market, with increase in profits by 200%, at 150USD opposed to a new player getting lower price.
- m. The representative of the exporter filing confidential data of importer shows a compensatory arrangement between the exporter and the importer and therefore such prices is required to be disregarded. Reliance is placed on Kumho decision of Designated Authority and CESTAT.
- n. The claims of the Applicant are totally distant from the law and practice of the Authority on multiple levels, especially with regards to onus of establishing claims. There are no merits in the claims made by the Applicant, until established by evidence, opposed to the Domestic Industry proving them otherwise.
- o. The exports made by the applicant are merely 2-3% of the total imports from China into India, which clearly shows that these transactions are stage managed.
- p. The exporter has grossly and intentionally suppressed information in the questionnaire response filed, including claimed expenses, basis and terms of sale.
- q. The importer has not filed a questionnaire response, but has just irregularly filed information as per its convenience with complete disregard of the law and practice of the Authority. The said information is not available in the public file either.
- r. DRI after conducting investigation found that the importers, including EXIM Corp. were overvaluing the product to evade anti-dumping duty. This raises serious questions on the reliability and credibility of the import price of these importers.
- s. The Applicant has filed for individual dumping margin without a claim or evidence for Normal Value, assuming that the Authority shall make efforts for the same.
- t. No clarification or claim has been given for MET by the exporter further complicating the determination of individual dumping margin. The Authority being quasi-judicial cannot hunt by itself for determination of normal value under Rule-7 as per the law.
- u. The domestic industry holds no obligation to come to the rescue of the applicant and make efforts in providing information relevant to determination of normal value.
- v. Since applicant has requested for individual margin of duty, the obligation is on the applicant to provide relevant information for determination of normal value with relevant evidence and supporting information of normal value and export price.
- w. In discharge of its obligation, the applicant has merely stated in its rejoinder submissions while replying to the arguments of the domestic industry, that the normal value should be determined on the basis of cost of production.

- x. The same is extremely belated at this stage of the investigation, where the Authority would go back to the stage of initiation and call relevant information from the domestic industry.
- y. By not providing any information on normal value, the exporters has in a way became non-cooperating in the present investigation, and the authority is required to terminate the investigations without giving individual duty.
- z. The Designated Authority holds no obligation to collect evidence of normal value and the applicant nowhere stated that it was not claiming normal value based on its data/information. Therefore the Authority can only terminate the investigations holding that there is insufficient information & evidence on record to determine dumping margin.
- aa. The Authorities have an obligation to make decisions on the basis of the best information available even where evidence has been supplied by the interested party, if the interested parties refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation. However, all reasonable steps should be taken by the authorities of the importing countries to avoid the use of information from unreliable sources. (WTO Egypt-Steel Rebar)
- bb. The Authority, in the absence of any information on normal value, has relied upon Qatar import price to India as per DGCI&S data.
- cc. The DGCI&S data is reliable information and is being used consistently by the Designated Authority. Also there has been no evidence contrary to the same.
- dd. Without prejudice to the above, use of export price from Qatar is not inappropriate in the facts & circumstances of the present case, for determination of normal value.
- ee. According to the hierarchy laid down in Para 7, the normal value shall be determined on the basis of the price from a third country to other countries, including India since no information has been provided by the applicant for constructed normal value in appropriate third country.
- ff. A comparison of practices applied by EU, US, Australia, Korea, Mexico and Brazil for determining appropriate third country shows the following broad factors used – (a) Scale of manufacturing and export from the analogue country, (b) Volume of imports from the analogue country, (c) Level of development, economic and product concerned, (d) Product produced in the analogue country, (e) manufacturing process, (f) Openness of the market, (g) Similarity in products.
- gg. It cannot be said that Qatar is not an appropriate surrogate country in the present case. Indeed, Qatar is the most appropriate market economy country.
- hh. Qatar is one of largest producer and exporter of the subject goods in the world and has the second highest exports of the subject goods to India, only below China PR.
- ii. The subject goods produced in Qatar are like products with the goods, and the manufacturing process is identical with the producers, in China PR and in India.
- jj. Moreover, Qatar is comparable to China PR in terms of level of economy and level of development of the product concerned and the market for production, sale and export for the product concerned is open in Qatar and free of any other non-market forces.
- kk. The domestic industry has no qualms for adopting import prices of other countries into India like Germany, Japan and UAE, since the import price from these countries are even higher than Qatar.
- ll. Factors like (a) Level of development of the product under consideration, (b) Production processes, (c) Scale of manufacturing, (d) Raw material availability are focused upon when normal value is based on domestic price, therefore the comparability of markets and price is very important.
- mm. Parameters relevant when the normal value is on the basis of price from third country to India are volumes of exports and the fact that the third country is not subject to dumping investigation. Market comparability of subject country and analogue country is not important since the price adopted is export price in India, therefore only Indian market is relevant.
- nn. Only when information with regard to cost or price in a market economy third country is not available, can price from market economy third country to other countries, including India be considered. If not, cost or price in India can be considered.
- oo. Under Rule 7, the precise hierarchy has been laid down. Thus, it is not permissible under the law to consider any methodology for normal value without exhausting the sequence.
- pp. The applicant has not contended how Qatar price is not appropriate or should not be adopted for export price to India. The country functions in the ordinary course of trade.

- qq. The investigation period holds absolute sanctity for determination of normal value and export price. Not only POI has been fixed in the instant case, but also, the Authority is barred from considering some data/information for the period beyond POI.
- rr. Decision of the Authority to use of data outside the POI for determination of normal value was challenged at the CESTAT and the decision was over turned in *Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. v. Designated Authority*.
- ss. The claim of applicant for use of cost in India for normal value is extremely belated and such a claim cannot be accepted at this stage of the investigation.
- tt. Moreover, the information and data pertaining to cost in India is not available with the Authority for the POI, and no new information can be brought on record at the given stage in the investigation.
- uu. The conduct of Applicant shows no intent to provide any information for determination of normal value, rather shows the belief that is the Authority that should hunt for such information.
- vv. Also, at this stage, the Designated Authority cannot ask domestic industry to provide information relating to determination of normal value.
- ww. The Authority has already issued the Disclosure Statement, and requesting the new information, along with preparation of the same working by the Domestic Industry followed by the analysis and due process of law, will add another three months to the investigation at the least.
- xx. Since the POI is non-financial year, the relevant information is not available in public domain either.
- yy. Also, the raw material constitutes only 45% of the total cost and hence only raw material indexation cannot be considered appropriated for the determination.

(ii) **Submissions made by the NSR applicant (producer/exporter)**

- a. Disclosure statement is the first communication by the authority that Qatar will be considered as a third country market economy for China. No details on the mandatory level of development have been provided.
- b. Para 7 provides level of development be taken into consideration based on reliable information. The Authority has relied on the quantum of imports from Qatar to India for such a selection, which is inappropriate.
- c. Qatar as a surrogate third market economy country is contrary to the approach in Para 7 and discriminatory to the Applicants.
- d. No relevant information or evidence on record with respect to the proposed selection of Qatar as surrogate country has been provided.
- e. It has been disclosed whether complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales and cost of production in Qatar is on record.
- f. Such information is mandatorily required by the Authority in past cases to construct the normal value on the basis of third country exports or prices.
- g. No such information/data is available in the present case nor has any attempt to get the relevant information from the suggested third country market economy been made either by the Domestic Industry or the Designated Authority.
- h. In such an absence, the Authority's proposal to take Qatar as a surrogate country is not in line with the legal provisions or its own consistent approach followed in the very same case.
- i. In the past investigations, the DGCI&S import data of third countries were present with the Authority. However, the Authority, considered the DGCI&S data as not appropriate to determine the normal value based on the third country market economy export prices.
- j. The most suitable way of calculation of normal value in a NSR investigation is to extend the methodology adopted by the Authority in the original as well as the sunset review investigations conducted by the Authority in the very same case. Any other methodology will lead to two sets of very different normal values for the exporters which will be discriminatory in nature.
- k. The Domestic Industry in the sunset review case stated that Normal Value cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available.
- l. Since the Authority was of the opinion of taking Qatar as a surrogate country and there is enough evidence on record for the same, the burden of proof to demonstrate the relevance and sufficiency of the same lies with the Authority. No information has been provided in that regards, and in absence of such data and information, the applicants are unable to offer any further comments.

- m. The Applicants requested for the rejoinder submissions of the Domestic Industry. However the Authority refused to share the same citing the past practice. The information contained in the rejoinder is of particular importance to the case as it has been used to select Qatar as an appropriate third country.
- n. Since the submission is not shared, the applicants are not in a position to offer their comments in an effective and reasonable manner.
- o. The level of development of Qatar is not comparable to that of China. The level of development of a country is measured by international organizations like UNDP, World Bank, IMF in terms of factors such as GDP per capita, Human Development Index, etc. The Authorities worldwide use such factors for comparison. However the disclosure statement does not suggest any such methodology that has been used.
- p. The disclosure statement is silent on the level of development of the Industry in the two countries and their comparability.
- q. Proposed selection of the third country market economy and the procedure followed is in complete contrast to the observations and the decision of the Hon'ble Supreme Court in the case of Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd.
- r. The selection of surrogate country for the determination of normal value is a process to be followed at the very beginning of the investigation. The Authority has not followed other procedures mandated for selection of third country market economy as well.
- s. A determination with regard to the ordinary course of trade and arms' length transactions cannot be made unless the complete and detailed data/information with respect to such surrogate country is on record and with the Authority.
- t. No hearing has been granted to the applicants with respect to the issue of taking Qatar as a surrogate country. Paucity of time cannot be reason for taking away the right of the applicant to be heard.
- u. Perusal of the list of NSR investigations shows the Authority has computed normal value for applicants from nonmarket economy on the basis of their cost-plus basis. There is no reason to deviate from this well-established practice of the Authority and on the ground of equality and equal protection of law.
- v. US authorities evaluate the economic comparability for selecting a surrogate country and the Australian anti-dumping manual provides for consideration of macroeconomics indicators to select the appropriate surrogate country. No such factor has been considered by the Authority in its proposal to consider Qatar as a surrogate country for China. There is a huge difference in the level of development indicators of Qatar and China.
- w. Taking Qatar as a surrogate country for China is against principles of equality and equal protection of law, against the Anti-dumping Rules and the Anti-dumping Agreement.
- x. Prices from Qatar are higher because the market prices in India are also higher to the extent of the anti-dumping duties on imports from China.
- y. To arrive at a fair realization in the Qatar market, the actual prices prevailing in Qatar should be taken or the CIF prices be adjusted to the extent of the anti-dumping duty applicable on imports from China.
- z. The ocean freight from Qatar to India also need to be revised to USD 64.47/MT from USD 40/MT.
- aa. Despite providing all the information of resale price by unrelated importer at the request of the Authority, the Authority proposed to take an approach contrary to past practice.
- bb. The information can be checked from the DGCI&S and DG System as was done for the transaction-wise exports made by the producer and exporter.
- cc. Consideration of export price of producer is directly in contradiction with the approach of the Authority taken in the case of Uncoated Copier Paper. In that investigation, responses of the exporters were rejected on the basis that the unrelated importers had not provided details. However such information is available in the instant case.
- dd. If the Authority wishes to consider the export price from producer, then also VAT needs to be adjusted to the ex-factory export price.
- ee. Importers (Para 14) had addressed the Authority during the oral hearing but did not submit any written submissions which is a mandatory requirement pursuant to the oral hearing. In the absence of any written submissions or claim, the Authority has proposed to rely upon certain information supplied by the said parties the copies of which have not been served to the applicant or made available in public file.
- ff. The Authority has not asked the other importers to provide any evidence to substantiate their claims while detailed information was called from the exporters as well as their importers. Clarification is required on whether such importers filed questionnaire responses or provided resale price information or bills of entry or any account ledger with the Authority.

- gg. It is to be seen why the importers, are supporting the Domestic Industry for imposition of anti-dumping duties. Also, one of the said two importers is facing DRI investigation for indulging in overvaluation of subject goods imported from China in order to avoid payment of anti-dumping duty leviable on such imports.
- hh. If any producer/exporter has not dumped the goods, it would be entitled to zero or lower duty. It is immaterial whether the dumping margin is determined as a part of the original investigations or is done in terms of Rule 22.
- ii. The exporter has given details of transactions, which has been verified by the Authority. Also, the importers have provided resale pricing information.
- jj. Other interested parties have not filed any evidence to the contrary questioning the export price of the applicants. In absence of such information the dumping margin should be calculated on the basis of the said information.
- kk. The export prices are most reasonable and genuine. There are several importers who have undervalued their imports possibly to take care of the existence of antidumping duties and some of these importers are also facing DRI investigations.

Comments by importers

(iii) M/s Sandeep Organics Pvt. Ltd.

- i. To Evade ADD, Indian importer, Chinese Exporter & Chinese producer has done over invoicing of PUC. It can be determined by high profits by the Chinese exporter.
- ii. Whereas, the Indian importer has sold PUC under profit, the importer has not considered liability of guarantee of ADD. If liability of guarantee of ADD is considered, PUC is sold at loss by the Indian importer.
- iii. Export declaration should be submitted to the Authority.
- iv. Other Chinese producer / Exporter data should be reconciled.
- v. Other Indian importer data should be reconciled.
- vi. Personal verification of Chinese exporter & Chinese producer should be done.
- vii. Provisional assessed & out of charge bill of entry to be submitted by the importer.
- viii. Auditor verified sale invoice, profit loss statement of PUC should be submitted along with purchase order / sales contract / proforma invoice / payment & other related documents.
- ix. Why exports of PUC in NSR were stopped after 31st December 2018?
- x. Importer have not paid ADD, it is loss to the government. They have just given the guarantee. Guarantee should have been mentioned on the accounting statements. Such related documents to be submitted.
- xi. Why only 2 importers are involved?
- xii. Misuse of law should not happen by taking undue advantage of loopholes in outdated NSR.

(iv) M/s Sunita Commercials Pvt. Ltd.

It appears that Authority is proposing to accord an individual dumping margin to this exporter. If so, our previous submissions and submissions made by the domestic industry, which adequately establishes that the credential of the exporter, the export price, the importers, the import price, everything as highly suspicious may be referred.

Since we have been regularly importing and selling Melamine in the country, we are well aware of the market activities and believe that this petition is an attempt to seek no or lower duty and therefore reject this request for individual duty.

F. Examination by the Authority

29. Computation of the Normal Value (NV)

The Authority notes the submissions made by various Interested Parties on the methodology of computing Normal Value and holds that the applicant Producer/Exporter seeking New Shipper Review did not file the Market Economy Treatment questionnaire to claim Market Economy Status, even though the Producer/Exporter had filed the applicant for grant of an individual Dumping Margin to them as per Rule 22. Therefore the Authority has to resort to the Para 7 of the Annexure 1 of the Anti- Dumping Rules to consider an appropriate Normal Value Methodology in the instant case. None of the Interested Parties including the applicant Producer/Exporter suggested a market economy third country for considering the price or constructed value in such a country. The Producer/Exporter, while choosing not to claim MET, at the same time did not suggest any market economy third country to consider applying the first proviso of para 7, either in the petition or when EQR was filed.

The second proviso of Para 7 of Annexure 1 suggests price from such a third country to other countries to other countries including India or where it is not possible on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted if necessary to include a reasonable profit margin.

In this regard the Authority notes that Para 7 further clarifies that “An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments”.

The Authority notes that it was only post Oral Hearing in February 2019 that the applicant Producer/Exporter suggested adoption of Constructed Normal Value methodology based on cost of production of India industry and the domestic industry suggested/adoption of imports from the third country i.e Qatar for computing the normal value. The Authority notes that besides submission on the basis of choice of the 3rd country market economy, the applicant producer/exporter have also contested that reasonable time and rejoinder copies have not been provided to them. The Authority notes that in an ‘NSR’ case as compared to an original investigation, where POI has been as prospective to enable the applicant producer/exporter to export in accordance with rule 22 of AD rules, the Authority only after applicant producer/exporter and other interested parties filed their submissions/responses as the case may be, could have provided its approach on adoption of the methodology for normal value. The Authority disclosed its approach in the disclosure statement dated 22/5/2019 and on request of the applicant producer/exporter also extended time to file comments as well till 7/6/2019. In the factual matrix of the case, the Authority holds that reasonable opportunity has been provided to the interested parties including the applicant producer/exporter to respond to the choice of methodology to determine the normal value. The Authority reiterates that rejoinder are not exchanged as per Authority’s consistent practice and that all such submissions were provided in the disclosure. Also the Authority has addressed all relevant submissions made post oral hearing and the disclosure and that no further hearing is considered necessary.

The Authority notes that the producer/exporter has stated that Authority has not followed the established process to select surrogate country which should be done at the beginning of the investigation. The Authority reiterates that this ‘NSR’ being an investigation on a prospective POI of 1 year and with completion period of 18 months, the count down starts only after the response is filed by the applicant producer/exporter. Authority could not have imagined that the applicant producer/exporter who has sought NSR would not file MET Questionnaire and nor would suggest any options prescribed under para 7 to annexure 1. The suggestions on normal value computation were made both by producer/exporter and the domestic industry post oral hearing which the Authority examined keeping in view the prescribed hierarchy in para 7 of Annexure 1 and various guiding judgements in this regard.

As regards Qatar not being an appropriate country for Normal Value in view of the level of development being different, the Authority holds that Qatar exports to India are next to China in terms of Quantum. The ‘level of development’ comparison as stated in para 7 of assumes relevance if prices and constructed value in Qatar is considered. Qatar’s export prices to India are not contingent on the level of development of Qatar but is established by benchmarking the prices of the domestic industry and other exporting countries to India. The last proviso of para 7 also requires consideration of price paid or payable in India. As Qatar happens to be a non dumped source with volume next to the subject country which is subjected to the levy of ADD to correct the unfair trade, its choice is appropriate as per para 7 (Annexure 1) provision of AD rules. The applicant Producer/Exporter has submitted that CIF price of import from Qatar be adjusted to an extent of ADD on import from China which the Authority holds is not justified as the import price from China has been corrected to a fair and non injurious level by the levy of ADD after adopting a due process as per rules. The export price from other sources also bench mark the corrected fair price from China.

The Authority further notes that the Producer/Exporter has thereafter also contested the ocean freight being adopted while computing exfactory export price of Qatar to India which is one of the adjustments to be considered for purpose of Normal Value computation. The Authority had proposed ocean freight based on the data available with it in one of the past investigations by an exporter from Qatar which was verified by the Authority. The evidence provided by the applicant was further correlated with the submissions and evidence provided by the Domestic Industry and Authority holds that the ocean freight considered by the Authority and stated in disclosure is reasonable and appropriate.

The Authority therefore confirms the methodology on Normal Value computation as stated in the disclosure and after allowing adjustments on ocean freight, port expenses, inland freight, credit cost, ocean insurance bank charges and additionally commission (1.5% of FOB) as submitted by the producer/exporter as per its consistent practice by adopting norms as is done consistently in similar/analogous situations from the CIF price from Qatar. The Authority confirms the ‘Normal value’ methodology incorporating aforesaid adjustments.

30. Ex-factory Export Price

The Authority notes that the applicant producer/exporter has submitted that VAT amount which has not been reimbursed to the exporter be adjusted and accordingly ex-factory export price be determined. The Authority holds that in the instant case, the questionnaire response of the exporter nor the producer lodge a claim for this adjustment. Further with the exporter's sales of subject goods having been identified as profitable, the producer's sales price to the exporter net of taxes (VAT) at ex-factory is therefore the relevant ex-factory export price for producer as the computation of dumping margin is carried out for the producer. The applicant producer/exporter has not submitted as to why this fundamental approach to evaluate ex-factory export price for producers is not appropriate especially when the exporter's price to India has been taken as profitable thereby indicating that producer to exporter price is reliable. The Authority therefore confirms the methodology and computation of ex-factory export price for the producer as mentioned in the disclosure as *** \$/MT.

The dumping margin for the producer based on the aforesaid is evaluated as (30-35%).

31. Other issues

The Authority notes submissions made by various interested parties on the aspect of over and under invoicing and that responses of importers other than buyers/importers from the applicant producer/exporter be obtained, and prices verified. The Authority notes that none of the importers have filed structured response to this investigation. While some data has been filed by the advocate for the producer/exporter for their two importers/buyers in India, no structured response has been filed even by them. The Authority for the purpose of examining the import price pattern of subject goods in India during POI obtained transaction wise data from DGCIS and as well as DG-Systems. The broad analysis of the same was also indicated in the disclosure.

As regards over invoicing, the Authority holds that it has evaluated the ex-factory export price of the producer as per its selling price to the exporter, the concerns on over invoicing by the exporter, if any, are taken care of.

32. Conclusions

- i. The Authority holds that quantity of export by the producer is quite reasonable to reference this sales to the exporter i.e M/s Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd (exporter) to evaluate the ex-factory price of export destined to India.
- ii. The producer has dumped the subject goods during the POI.
- iii. As per rule 22, the extent of dumping margin as stated above in para 30 is awarded to the producer i.e M/s Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd (Producer) as the Anti-dumping duty.

33. Recommendations

In view of the above, the ADD stated in duty table below is recommended in respect of parties mentioned below:

All other aspects of duty imposed vide C.No. No. 2/2016-Customs (ADD) dated 28/1/2016 remains unchanged.

Duty Table

Sl. No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
1.	29336100	Melamine	China PR	China PR	M/s. Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd.	M/s Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd.	319.04	MT	US\$
2	29336100	Melamine	China PR	China PR	M/s. Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd.	Any other than M/s Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd.	331.10	MT	US\$

3.	29336100	Melamine	China PR	Any country other than China PR	M/s. Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd.	Any	331.10	MT	US\$
----	----------	----------	----------	---------------------------------	---	-----	--------	----	------

34. Exports made by M/s Foshan Kaisino Building Material Co., Ltd (exporter) of goods produced by M/s Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd (Producer) in pursuance of C.No. No. 11/2018-Customs (ADD) dated 20/3/2018 may be regularised as per the AD recommended in para 33 above. This duty is coterminous with the AD duty imposed vide C.No. No. 2/2016-Customs (ADD) dated 28/1/2016.

35. **Further Procedure**

An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this Final Finding Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Add. Secy. & Director General